

कारिणी समिति का आरंभ ६९, कार्यकारिणी का क्रमविकास ७०-७३, १८३३ का एक्ट ७१, १८६१ का एक्ट ७१, लार्ड कैनिंग और विभागों का पृथक्करण ७२, प्रान्तीय सरकारों के आय-व्यय के अधिकार का आरंभ ७२, दिल्ली दरबार ७३, १९१९ का एक्ट केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषय-विच्छेद ७३, प्रान्तीय विषय ७३-७४, समर्पित विषय ७३-७४, सुरक्षित विषय ७४-७५, केन्द्रीय विषय ७५-७६, १९३५ के एक्ट द्वारा परिवर्तन ७६-७७, बायसराय और कार्यकारिणी ७७, १९३५ के एक्ट द्वारा परिस्थिति ७७-७८, प्रान्तीय कार्यकारिणी ७८, मंत्री ७९-८०, १९३५ के एक्ट द्वारा परिवर्तन ८०, मंत्रियों का उत्तरदायित्व ८०-८१, एडवोकेट जनरल ८१, गवर्नर और उसके अधिकार ८१-८२, जिला और शासन-प्रबंध ८२-८५।

पाँचवाँ अध्याय — गवर्नमेंट का आय-व्यय और बजट—
८६-१०४—

१८३३ में आर्थिक नियंत्रण ८६. जेम्स विल्सन और सुधारयोजना ८७. लार्ड मेयो और सुधार ८८. जानस्ट्राची और आर्थिक नीति ८८. लार्ड कर्जन की आर्थिक नीति ८९. मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रान्तीय सरकार के आय-व्यय का पृथक्करण ८९. केन्द्र सरकार की आय ९०-९५. केन्द्रिक शासन का व्यय ९५-९८. प्रान्तीय सरकारों की आमदनी ९७-९९. प्रान्तीय व्यय ९९-१०१. बजट १०१-१०४. बजट कैसे पास होता है १०२-१०४।

ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿਚ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ

केन्द्रीय शासन १०२ विभाग-विभाग १०३ विभाग १०४
विभाग १०५-१०६ अधीनस्थान १०७ विभाग-विभाग १०८
विभाग १०९-११० व्यापार-विभाग १११ विभाग-अधिकांश विभाग
११२-११३ कानून-विभाग ११४ विभाग-विभाग ११५ विभाग ११६
११७ डिप्टी कमिशनर या कलेक्टर ११८

आपनी ईर्ष्या-लेश नष्ट हो गया। निम्नलिखित अर्थ में परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष से सनको जहाज पंगेवों ने अपना आधिपत्य जमा किया।

अंग्रेजों ने यद्यपि पहले भी भारत में पहुँचने के कुछ प्रयत्न किये हैं किन्तु उनको सफलता नहीं हुई। कुछ अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत में आये और उन्होंने यहाँ का जो नृनान्त मुनागा उसमें डैंगलेण्ड में अधिक उत्साह बढ़ा। कुछ सीढागरों ने सन् १५१५ में मिलकर बन्दा करके एक नौसेना पूँजी इकट्ठी कर ली और डैंगलेण्ड की महारानी एलिजबेथ से प्रार्थना की कि उनको ईस्ट इन्डिज में व्यापार करने का अधिकार-पत्र प्रदान किया जाय। सन् १६०० के अन्तिम दिनांक को उनको अधिकार मिल गया। इस व्यापार समिति का नाम “The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies.” निश्चित हुआ और उसे १५ वर्ष के लिए व्यापार करने का अखण्ड अधिकार दे दिया गया। यह व्यापारी कम्पनी एक गवर्नर और चौबीस सदस्यों की थी।

अनेक अड़चनों और विरोध के होने पर भी इस कम्पनी ने अपने व्यापारी जहाज नौ बार भेजे। यद्यपि कुछ जहाज टूटे-फूटे, किन्तु व्यापार में कम्पनी को लाभ ही हुआ। इसी कम्पनी की ओर में कैप्टन हाकिम आया था जिसने सन् १६०८ में मूरत में भारत के साथ अंग्रेजी व्यापार स्थापित करने का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयत्न किया। वह मोगल सम्राट जहाँगीर से मिला और मूरत में अंग्रेजों के रहने की आज्ञा प्राप्त कर ली। किन्तु पुर्तगाल वालों के विरोध से यह आज्ञा रद्द हो गई।

चार वर्ष बाद (१६१२) कैप्टन वेस्ट कम्पनी के जहाज लेकर मूरत आया। उसने पुर्तगाल वालों को हराकर अंग्रेजों का महत्व ऐसा बढ़ा दिया जिससे उनको मूरत में अपनी फैक्टरी बनाने की आज्ञा सम्राट ने मिल गई। वस उसी समय से जो भारत का अंग्रेजों से सम्बन्ध स्थापित

अंग्रेजों ने हिन्दुशासन के टापुओं में ध्यान देकर अपनी पूरी शक्ति भारतीय व्यवसाय बढ़ाने में ही लगा दी। उसने उन्होंने भारत में शीघ्रता के साथ उद्योग करना आरंभ कर दिया।

सर टामस रो की निर्धोग्नि नीति पर अंग्रेज १६८६ तक चलते रहे। इस काल (१६१२-८६) में उन्होंने अपना व्यवसाय अच्छी तरह बढ़ा लिया। भारत के पश्चिमी तट के अलावा उन्होंने पूर्वी तट पर भी अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिये। सन् १६११ में कंटेन द्वीप के ममुलीपट्टम में कोठी कायम की। बावजूद यह तक तो यहाँ अच्छा व्यापार चला किन्तु फिर ऐसा घटा कि उसको छोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। अन्त में पूर्वी तट का व्यापारिक केन्द्र चेन्नापटम (मद्रास) में कायम किया गया जिसको सन् १६८० में फ्रांसिस डे ने चन्द्रागिरि के राजा से लिया। यहाँ पर उसे संगीत कोठी बनाने की आज्ञा मिल गई। यही कोठी मेदजाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला अंग्रेजों का सबसे पहला किला भारतवर्ष में बना।

ममुलीपट्टम के उत्तरी भाग में भी बाज्रने हुए कार्टगुट नामक एक अंग्रेज उड़ीसा पहुँचा। सन् १६३३ में टाग्लरपुर और बालासोर में उसने व्यापार जमाया। सन् १६५० में बंगाल के मुबदार ने कम्पनी के हुगली में अपनी कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। कुछ समय के बाद उन्होंने कामिस बाजार और पटना में भी कार्टिया बनाई। उड़ीसा और बंगाल में कम्पनी की अधिक व्यापारिक सकलता नहीं हो सकी किन्तु 'रिम्स' के निर्माण प्रकार से वहाँ पर अदे हो रहा।

सन् १६३० से १६८० तक का समय कम्पनी के लिए स्वर्णयुग के समान सिद्ध हुआ। इस काल में उसका व्यापार ने अत्यन्त लाभ हुआ। हुगली के राजा बालम द्वितीय की भी इस पर हताशा हुई। इस सन् १६३८ में कम्पनी की कबड १ पण्ड मादराजसरी पर बम्बई के 'रिम्स' कम्पनी ने पश्चिमी तट का बहुत मुक्त में देकर बम्बई में स्थापित क

दिया। इस काल में कम्पनी का डच लोगों से भी झगड़ा न रहा क्योंकि वे फ्रांसीसियों से लड़ने में दत्तचित्त थे।

किन्तु इस काल में सबसे मार्के की बात जो हुई वह यह है कि इंगलैंड के राजा ने कम्पनी को क़िला बनाने एवं उनकी रक्षा करने, सैनिकों को भर्ती करने, लड़ाई के जहाज़ रखने, सिक्का ढालने, और फ़ौजदारी एवं दीवानी कानून के अनुसार अंग्रेज़ों पर न्याय करने के अधिकार प्रदान कर दिये। यही नहीं, भारत में प्राप्त अंग्रेज़ी रियासत का शासन करने के लिए कम्पनी इंगलैंड के राजा की प्रतिनिधि नियुक्त कर दी गई। इसके अलावा उनको युद्ध ठानने अथवा सन्धि करने, और ईसाइयों को छोड़कर अन्य लोगों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। इन्हीं अधिकारों से भारत में अंग्रेज़ी शासन और विधान का सूत्रपात होता है। इन्हीं से कम्पनी को वे अधिकार प्राप्त हो गये जिनके बल पर कम्पनी ने अपना शासन भारतवर्ष पर धीरे धीरे ऐसा जमाया कि वे इस देश के स्वामी हो गये।

व्यापार और आत्मशक्ति की वृद्धि ने कम्पनी के भावों और आदर्शों में भी परिवर्तन होने लगा। इनके सिवा भारतवर्ष की राजनैतिक परिस्थिति की भीषणता ने भी उनके विचारों पर प्रभाव डाला। मुगल सम्राट औरंगज़ेब के समय में दक्षिण में बड़ा विप्लव और उथल-पुथल हो रहा था। शासन के बन्द डीले हो रहे थे। लूट-मार का वाजार गर्म था। ऐसी दशा में अपनी रक्षा करने के लिए एक सामरिक परिवर्तन में लाभ उठाने के लिए कम्पनी को भी अपनी नीति के बदलने की आवश्यकता ज़रूर पाने लगी। मुगलान में शासन की नीति का परिवर्तन करना ही एक समस्या और आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए १७०० के समय में

महाराजा साहू ने इस नीति में बदलाव करवाया और मुगल शासन पर प्रभावशाली प्रतिक्रिया का कारण बन गया। इस परिवर्तन के कारण कम्पनी का स्वयं व्यापारिक लाभ, न सिर्फ़ उच्च समझ आ गया बल्कि उच्च शासन के

कम्पनियों की समस्याओं को सुलझाकर और उनमें समझौता कराके सन् १७०८ में अर्ल गोडालिफन ने एक संयुक्त कम्पनी की संस्थापना कर दी जिसमें पुरानी कम्पनी का व्यक्तित्व और विस्तृत रूप में प्रस्फुटित हो गया। इस संयुक्त संस्था का नाम "United Company of merchants trading to the East Indies." हुआ। वस यही कम्पनी भविष्य में सन् १८५७ तक व्यापार एवं शासन का कार्य करती रही यद्यपि उसके अधिकारों में समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते रहे।

सन् १६९४ में एक और भी ध्यान में रखने योग्य घटना हुई। इस सन् के पहले व्यापार का ठेका आदि देने का अधिकार इंग्लैंड के राजा ही के हाथ में था किन्तु सन् १६९४ में हाउस ऑफ़ कामन्स ने वह अधिकार राजा से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। यह घटना इस लिए महत्त्व की है कि उस समय ने पार्लमेंट का सम्यन्ध कम्पनी ने बाधम हो गया और वह भविष्य में बढ़ता गया। पार्लमेंट ने आरम्भ में कम्पनी के अधिकारों और उसकी नीति में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया किन्तु धीरे धीरे वह तटस्थ न रह सकी।

इस कम्पनी का उन्निहान्त सुझावों के लिए तीन अकों में विभाजित किया गया है। पहला अक अष्टादहवीं शताब्दी के मध्यकाल तक चलता है। दूसरा कम्पनी मरदान व्यापार में ही रखा गया। दूसरा अक अष्टादहवीं शताब्दी के मध्य में लेकर देवदत्त शताब्दी तक चलता है। तृतीय अक अष्टादहवीं शताब्दी के मध्य में लेकर देवदत्त शताब्दी तक चलता है।

कम्पनियों की समस्याओं को सुलझाकर और उनमें समझौता कराके सन् १७०८ में अर्ल गोडाल्फिन ने एक संयुक्त कम्पनी की संस्थापना कर दी जिसमें पुरानी कम्पनी का व्यक्तित्व और विस्तृत रूप में प्रस्फुटित हो गया। इस संयुक्त संस्था का नाम "United Company of merchants trading to the East Indies." हुआ। वस यही कम्पनी भविष्य में सन् १८५७ तक व्यापार एवं शान्त का कार्य करती रही यद्यपि उसके अधिकारों में समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते रहे।

सन् १६९४ में एक और भी ध्यान में रखने योग्य घटना हुई। इस सन् के पहले व्यापार का ठेका आदि देने का अधिकार इंग्लैंड के राजा ही के हाथ में था किन्तु सन् १६९४ में हाउस ऑफ़ कामन्स ने वह अधिकार राजा से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। यह घटना इस लिए महत्त्व की है कि उस समय ने पार्लमेंट का सम्बन्ध कम्पनी में कायम हो गया और वह भविष्य में बढ़ता गया। पार्लमेंट ने आरम्भ में कम्पनी के अधिकारों और उसकी नीति में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया किन्तु धीरे धीरे वह तदर्थ न रह गयी।

इन कम्पनी का इतिहास मुभीति के लिए तीन अंकों में विभाजित किया गया है। पहला अंक अष्टादशी शताब्दी के मध्यकाल तक चलता है। इसमें कम्पनी मुख्यतः व्यापार में ही लगी रही। दूसरा अंक अष्टादशी शताब्दी के मध्य में लेकर रेगुलेशन एक्ट (१७७३) तक। इसमें कम्पनी के राज्य या विस्तार होना है। उनका व्यापारिक कार्य गौण होना और शान्त कार्य

उड़ीसा का शासन करने के अलावा और प्रेसीडेन्सियों की राजनैतिक कार्यवाहियों का भी निरीक्षण और नियंत्रण करने लगी। प्रत्येक विषय काउन्सिल के बहुमत के अनुसार ही निर्णय होना, और बराबर वोट होनेपर गवर्नरजनरल को अपना निर्णायक वोट देने का अधिकार था। इस एक्ट में गवर्नरजनरल और काउन्सिल को यह भी अधिकार मिला कि वे ऐसे कानून, विधान और नियम बना सकें जिसमें शासन का सुधार और साधारण जनता को लाभ हो, जो अंग्रेजी कानूनी सिद्धान्तों पर अवलम्बित हों किन्तु ये कानून, नियम आदि जब तक न्याय की सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर न हो जाते तब तक प्रचलित नहीं हो सकने थे।

इस एक्ट के द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीमकोर्ट की भी संस्थापना की गई जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में न्याय का कार्य देखे। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा तीन और भी जज नियुक्त हुए जो विलायत में कम से कम पाँच वर्ष वैरिस्टरी कर चुके हों। इन कोर्ट को फौजदारी, दीवानी, नौ विभाग और धर्म विभाग के मामलों के निर्णय करने का अधिकार दे दिया गया। वे अपनी सहायता के लिए क्लर्क आदि नियुक्त कर सकने और ऐसे नियम और कार्यक्रम निश्चित कर सकने थे जिनमें न्याय करने में सहायता मिल सके।

इस एक्ट के द्वारा अनुचित लाभ और रिश्वतों के रोकने का भी प्रयत्न किया गया। गवर्नरजनरल, काउन्सिल के मेम्बर, चीफ जस्टिस और जजों की भारी तनखाहें कर दी गईं। उदाहरण के लिए बंगाल के गवर्नर का वार्षिक वेतन पहले केवल ३०० पाँड और काउन्सिल के सदस्यों का अस्सी पाँड था किन्तु अब उनका वेतन क्रमशः २५,००० और १,०००० पाँड वार्षिक कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि वे आर्थिक चिन्ता अथवा प्रलोभनों से मुक्त हो जायें।

रेग्यूलेशन एक्ट के दोष—यद्यपि एक्ट बनानेवालों का उद्देश्य सराहनीय और सुधारमूलक ही था किन्तु अनुभव एवं परिस्थिति का पूर्ण

इसका और भी कई प्रकार में अधिकार है। भारत सरकार को शासन संबंधी कार्यों की रिपोर्टें भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती हैं। कई कार्यों के लिये तो भारत सचिव की अनुमति पहले ही ले लेनी पड़ती है जैसे युद्ध, संधि इत्यादि। आजकल प्रायः सभी कार्यों के लिये अनुमति लेनी पड़ती है। मन्त्रों जनरल के द्वारा भारत सचिव प्रांतीय सरकारों के कार्यों का भी निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है। इस प्रकार शासन प्रबंध संबंधी मामलों में हर तरह से भारत सचिव निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है।

धन सम्बन्धी अधिकार—सन् १९२० के पूर्ण एजन्सी का कार्य, जैसे भारत सरकार के लिये माल-अमवाय गरीदना, कर्जा लेना, ढेके देना आदि भारत सचिव के ही हाथ में था, किन्तु अब इस कार्य के लिये भारत सरकार की ओर से 'हार्ड कमिशनर' नियत किया गया है। एजन्सी का काम भारत सचिव के हाथ में न होने पर भी उसके अर्थ संबंधी अधिकार महत्वपूर्ण हैं। भारत सचिव अब भी बड़े कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि एवं मालगुजारी, और सैनिक व्यय और भारत के सम्राट् की हंसियत से सम्राट् की सम्पत्ति का नियंत्रण करता है। यदि कोई नया टैक्स लगाने या घटाने की आवश्यकता पड़ती है तो भारत सरकार के लिये भारत सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य सा है।

कानून संबंधी अधिकार—भारत सरकार व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये हुए कानून को सम्राट् की स्वीकृति के लिये सम्राट् के पास भेजती है। यह स्वीकृति भारत सचिव ही सम्राट् को आंग में दिया करते हैं। यदि भारत सचिव किसी कानून को नामज़ूर करे तो वह कानून जारी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार को हर एक कानून के संबंध की रिपोर्ट (Report) भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती है। भारत सचिव की अनुमति बिना भारतीय व्यवस्थापिका कुछ विषयों—जैसे हाईकोर्ट को तोड़ना या नई निर्माण करना, हाईकोर्ट के सिवा अन्य

अदालत को किसी यूरोपियन के मृत्यु-दंड का अधिकार देना आदि—पर कानून नहीं बना सकती। इस प्रकार भारत सचिव का कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण अधिकार है।

भारत सचिव और इंडिया काउंसिल—यह लिखा जा चुका है कि इंडिया काउंसिल का मुख्य कार्य भारत सचिव को अपने परामर्श से सहायता पहुँचाना था। बहुत ही गोपनीय तथा अत्यंत शीघ्रता के कार्यों को छोड़ कर प्रायः सब कार्य भारत सचिव इसी काउंसिल के साथ ही करता है। काउंसिल की बहुमति बिना उसे भारतीय आय को व्यय करने या भारतीय संपत्ति को बेचने एवं भारत के लिये ऋण लेने का अधिकार नहीं है। बड़े बड़े कर्मचारी (I.C.S.) की छुट्टी के नियम में परिवर्तन तथा हिन्दुस्थानियों को ऊँचे पदों पर नियत करने में भी काउंसिल की बहुमति अनिवार्य है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भारत सचिव अत्यंत आवश्यक समझ कर काउंसिल की सलाह बिना ही कर सकता है। ये विषय हैं—बाहिरी देशों से संधि या विग्रह तथा भारतीय रियासतों से संबंध रखने वाले। इसके अनिश्चित भारत सचिव को अपनी काउंसिल के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार भी असाधारण परिस्थिति में है।

सन् १९३५ के रक्त के अनुसार इंडिया काउन्सिल तोड़ दी जायगी उसके बदले भारत सचिव के तहत में छ व्यक्तिओ की समिति स्थापित किया जाएगा इसको स्वतन्त्रता है किजसे वह प्रत्येक से अलाहदा २ अथवा एक साथ परामर्श के लिए जाये बिबुद्ध सलाह न ले। इन सलाहकारों में से आधे ऐसे होंगा जहाँ 'क' जगहों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में सरकार की नौकरों की हों। भारत सचिव सलाहकारों की नजर पर नज़रों को बाध्य न होगा केवल सरकारी नौकरी के मामलों में उसको बहुमत का आदेश करना होगा इस परिवर्तन से सत्रेडर आफ स्टेट का पट्टे की ओर अधिकार कुछ बढ़ जायगा।

आर्डिनेंस कहते हैं। आर्डिनेंस की अवधि ६ माह तक रहती है किन्तु यदि गवर्नर जनरल चाहे तो उसे रह भी कर सकता है।

सन् १९३५ के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल का कर्तव्य होगा कि वह भारत की आर्थिक साख की रक्षा करे जिससे अन्यान्य देशों में भारत की साख-रक्षा की धाक बिगड़ने न पाये। इसीलिये उसको अधिकार दिया गया है कि वह भारत को ऐसे काम न करने दे, जिससे वर्मा और ब्रिटेन के व्यापार पर ऐसे प्रतिबन्ध लगें जो दूसरों के मुकाबले में कठोर और असमान हों। आर्थिक विषयों पर परामर्श लेने के लिये यदि वह चाहे तो एक अर्थ सचिव (Financial Adviser) नियुक्त कर सकता है। उसकी अनुमति बिना धन व्यय या नये टैक्स से संबंध रखता हुआ कोई भी मसविदा (Bill) व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका के बहुमत के विरुद्ध बजट का कोई भी भाग गवर्नर जनरल अपने ही विशेष अधिकार से पास कर सकता है।

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति—१९१९ के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती थी। आजकल इसकी संख्या ८ है। समिति के सदस्य सम्राट् ५ वर्ष के लिये ही नियत करने हैं, किन्तु आवश्यकतानुसार इनकी अवधि में परिवर्तन हो सकता है। सन् १९०९ के पूर्व इसके सब सदस्य अंग्रेज ही थे। सन् १९०९ में लार्ड माले ने, जो उस समय भारत सचिव थे, सर सत्येन्द्र प्रमन्न मिश्रा (बाद में लार्ड मिश्रा) को इस समिति का सदस्य बनाया। लार्ड माले के इस कार्य की अत्यंत नीत्र आलोचना हुई। आलोचकों का कथन था कि भारतवासी अभी इस योग्य नहीं हुए हैं कि वे इस उच्च पद को संभाल सकें। इसके अनिश्चित उन्हें यह भी अंदेशा था कि सरकार की गुप्त बातें भारतवासियों को ज्ञात हो जावेंगी। सर सत्येन्द्र ने बड़ी योग्यता से कार्य कर दिखा दिया कि भारतवासी भी

और उड़ीसा प्रान्तों की रचना सन् १९३५ के एक्ट के द्वारा ही हुई है।

बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसीडेन्सी आरम्भ से ही बन चुकी थीं। मद्रास प्रान्त का आधुनिक रूप १७९९ में टीपू मुल्तान की पराजय से प्रायः निश्चित हो चुका था। तृतीय मराठा युद्ध (१८१८) के बाद बम्बई प्रान्त सिंध प्रदेश को छोड़ कर बन गया था। सन् १८१८ तक सिंध, पंजाब, बर्मा और आसाम के सिवा प्रायः समस्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य या रक्षा में आ चुका था। कम्पनी का राज्य ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों प्रान्तों को विभक्त करने की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी। समय समय पर प्रान्तों की रचना होती गई जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है।

यू० पी०—सन् १८३३ के एक्ट के अनुसार आगरा प्रान्त (नार्य-वेस्ट प्राविस के नाम से) बना कर लेफ्टनेंट गवर्नर के आधीन किया गया। सन् १८५६ में अवध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर एक चीफ कमिश्नर के आधीन किया गया। सन् १८७७ ईस्वी में अवध और आगरा प्रान्त मिलाकर लेफ्टनेंट गवर्नर के आधीन रखे गये। सन् १९०२ में इस प्रान्त का आधुनिक नाम पड़ा और सन् १९१९ के एक्ट के अनुसार यह गवर्नर के आधीन हुआ।

पंजाब*—१८४९ ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब जीत कर एक बोर्ड के आधीन रखा। कुछ समय बाद पंजाब चीफ कमिश्नर के आधीन हुआ। १८५९ में दिल्ली भी पंजाब में मिला दिया गया और चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टनेंट गवर्नर रखा गया। सन् १९१२ के दरबार के बाद

* पंजाब विजय के पहिले सिंध जीत कर बंबई प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया।



सम्राट् ने भारतवासियों की मांगों पर विचार करने तथा उन्हें क्यासंभव पूरा करने का एक प्रकार से वादा कर दिया। भारत का विभिन्न समाज अगिल भारतीय नेशनल कांग्रेस आदि संस्थाओं स्वराज्य (Home-rule) एवं औपनिवेशिक (Colonial) ढंग के राज्य (Dominion Status) की मांग करने लगीं। कांग्रेस आन्दोलन ने पुनः जोर पकड़ा। हिन्दू-मुसलमान, नरम और गरम दल मिलकर एक स्वर से स्वराज्य मांगने लगे। आन्दोलन की उग्रता, आपत्तिकाल और मांगों के औचित्य का विचार करके एवं महायुद्ध में भारतीयों द्वारा किये हुए बलिदानों का ध्यान रख, उनसे प्रसन्न होकर सन् १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि सम्राट् की नीति भारतवर्ष को स्वशासन और उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन के लिये क्रमशः तैयार करना है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिकाधिक शामिल किया जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई मंजिलें तय करनी पड़ेंगी। प्रत्येक मंजिल पर पहुँचने का समय और उसके माधन निर्दिष्ट करने का अधिकार ब्रिटेन और भारत की सरकार के हाथों में रहेगा, क्योंकि भारत की प्रजा के उत्कर्ष और समृद्धि का भार उनके ही ऊपर है। भारत के सामन समय से अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। इसका महत्त्व यह है कि सरकार ने भारतवासियों को उत्तरदायित्व पूर्ण स्वशासन देना स्वीकृत कर उनकी मांगों के औचित्य को स्वीकार कर लिया।

उपरोक्त घोषणा के पश्चात् भारत सचिव माननीय मॉन्टेग्घ भारत की परिस्थिति समझने तथा जाँचने के लिए भारत में आये। उन्होंने देश के नेताओं तथा अन्यान्य संस्थाओं एवं दलों के प्रधानों से और सरकारी अफसरों से मिलकर जाँच की। तत्पश्चात् उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली जिसे Montague Chemsford Report कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश पार्लमेण्ट में एक बिल उपस्थित किया गया जो पार होने के बाद Government of India Act of 1919 कहलाया।

एक्ट के अनुसार इंग्लैंड की तरह दो सभाएँ बनाई गईं। ऊँची सभा (Upper House) को राज्यपरिषद (Council of State) कहते हैं। और दूसरी सभा या पुरानी व्यवस्थापिका सभा 'लेजिस्लेटिव असेंबली' (Legislative Assembly) कहलाती है। काउन्सिल ऑफ़ स्टेट या राज्य परिषद विद्या, सार्वजनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त तथा उच्च समाज के प्रतिनिधित्व के लिए ही विशेष रूप से निर्माण की गई है। इसके सदस्यों की संख्या ६० रखी गई जिनमें से ३४ चुने हुए तथा २६ गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किये जाते हैं। इन नामजद सदस्यों में से २० से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते। चुनाव का अधिकार माली हालत के अनुसार (Property Qualification) ही रखा गया है; अतएव वनाढ्य व्यक्ति ही मत दे सकते हैं। राज्यपरिषद की अवधि का समय ५ वर्ष है।

१९१९ के एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभा में ६० से संख्या बढ़ाकर १४४ कर दी गई जिनमें से १०४* जनता द्वारा चुने हुए और सरकारी प्रतिनिधि तथा ४० नामजद सदस्य हैं। चुनाव के संबंध में १९०९ के एक्ट के ही अनुसार धर्म और जाति के सिद्धान्त पर निर्वाचक संघ बनाये गये हैं। ४० सदस्यों में से २६ से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते। वायसराय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को किसी एक सभा का सदस्य नामजद कर देता है। कार्यकारिणी का वह सदस्य जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नामजद किया गया हो काउन्सिल ऑफ़ स्टेट का सदस्य नहीं हो सकता। वह केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही में वोट

* १०४ निर्वाचित में से ५२ सार्वजनिक या और मुसलमान, ३० मुसलमान, २ सिक्ख, ७ जमींदार, ९ यूरोपियन, ४ व्यापारिक मंडल (Indian Chamber of Commerce)

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में द्विविध शामन के आरंभ होने से विशेष परिवर्तन हो गया है। प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउंसिल समर्पित (Transferred) प्रान्तीय मामलों में क़ानून बनाती है। गवर्नर उसी व्यक्ति को मंत्री बनाता है जिसके अनुयायी प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुतायत से होते हैं। मंत्री काउंसिल के निकट उत्तरदायी है*। सन् १९१९ के एक्ट में १९१७ की घोषणा के आधार पर एक बार यह स्वी गई कि दस वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लमेंट भारतीयों की परिस्थिति जाँचने के लिये एक कमीशन नियत करेगी। इसी के अनुसार सन् १९२७ में माइमन कमीशन का आगमन हुआ। कई कारणों से नियत समय के दो वर्ष पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने इसकी नियुक्ति कर दी।

१९१९ के एक्ट ने यद्यपि कुछ अंशों में उत्तरदायी शामन (Responsible) आरंभ कर दिया, तथापि प्रजा इन मुद्धारों में संतुष्ट न हुई। प्रजा को अधिक आशाएँ थीं। एक्ट ने उन्हें बहुत ही कम मुद्धार दिये। नरम दल वालों ने अग्रणीय दर्शाने हुए भी मुद्धारों को स्वीकार कर लिया किन्तु गरमदल वाले चुप न रह सके। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ना ही रहा। सन् १९२१ में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में गत्याग्रह आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ा। सन् १९१९ के मुद्धार भी जागी न किये जा सके। किन्तु अब सन् १९३१ में नई व्यवस्थानुकूल शामन प्रणाली लागू हुई।

जनता द्वारा निर्वाचन का क्रमविकास—उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि भारतीय व्यवस्थापिका का आरंभ १८५३ में हुआ। उस समय ३ सदस्य नामित हुए। १८६१ के एक्ट में १२ में से ६ सदस्य सरकारी सदस्य नियुक्त हुए। १८९२ के एक्ट के अनुसार

* इसका विस्तृत वर्णन अगले परिच्छेद में देखिए।

सूत्रों की व्यवस्थापिका सभाओं में जो विल पास होंगे वे गवर्नर की स्वीकृति के लिए रखे जायेंगे। वह चाहे स्वीकृति दे चाहे न दे और चाहे तो गवर्नर जनरल के पास स्वीकृति के लिए भेजदे। गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलने पर भी सम्राट् को अधिकार है कि वारह महीने के भीतर उसे रद्द करदे।

चुनाव के नियम—ऊपर कहा जा चुका है कि चुनाव का मिश्रित सन् १८९२ के सुधारों ने उपस्थित किया था। एकट में यद्यपि चुनाव के विषय में कोई धारा नहीं थी किन्तु सरकार का अभिप्राय Indirect Election द्वारा ही काउंसिलों के गैर सरकारी सदस्यों को नियत करना था। अतएव १८९२ के क़ायदों के अनुसार म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड आदि लोकल मंस्थाओं के गैर सरकारी सदस्यों को प्रान्तीय सभा के लिये प्रतिनिधि चुनने का हक दे दिया गया था। उन चुने हुए प्रतिनिधियों के नाम सरकार की मंजूरी के लिये भेज दिये जाते थे। इसी प्रकार प्रान्तीय सभायें केन्द्रीय सभा के लिये चुनती थी और उत्तीर्ण व्यक्तियों के नाम गवर्नर जनरल के पास भेजती थी। मिन्टो मार्ले रिफ़ॉर्म ने खुल्लम खुल्ला 'जनता द्वारा चुनाव' (System of Direct Election) आरंभ किया। सन् १९०९ के सुधारों ने तीन प्रकार के निर्वाचक संघ बनाये (१) सार्वजनिक (General) जिनमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका के या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड म्यूनिसिपैलिटी आदि लोकल मंस्थाओं के गैर सरकारी सदस्य थे। (२) वर्ग विशेष (Class Electorates) जिनमें (अ) जमींदार (ब) मुसलमान निर्वाचक संघ तथा (३) ग्राम या विशेष निर्वाचक संघ (Special Electorates) जैसे मनिफैस्ट्री, नेम्बर आफ़ कान्ग्रेस, प्रेमीडन्मी कार्पोरेशन आदि थे उसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव के लिये भी व्यवस्था हो गई। सन् १९१९ के एक्ट ने करीब ७३ लाख व्यक्तियों की प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था। यह मंस्था भारत की जन मंस्था का करीब $\frac{1}{3}$ भाग है। उसीके अन्तर्गत

सकना है जो १०,०००) में २०,०००) * की आमदनी पर इनकमटैक्स देना हो या कम से कम ३५०) में ५,०००) मालाना लगान देना हो। उनके अलावा मार्गजनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त, म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, यूनियनिटी सोसिटी के सदस्य या जिन सरकार द्वारा विद्वाना के लिये उपाधियाँ मिली हैं, मार्गजनिक निरीक्षक संघ (General Constituency) के वोटर्स में आना नाम लिया सकते हैं।

भारतीय व्यवस्थापिका (Legislative Assembly)—उनके चुनाव में मत देने का अधिकार उन्हीं को है जो (१) कम से कम १५) में २०) तक मालाना म्युनिसिपैलिटी को कर देने हैं या (२) ऐसे मकान में रहते हैं या मकान के मालिक हैं जिनका १८०) मालाना किया हो, या (३) कम से कम १०००) में ५,०००) तक आमदनी पर इनकमटैक्स देने हों या (४) कम से कम ५०) में १५०) तक मालाना मरक़ारी लगान देते हैं। हर एक प्रान्त में एक भा नियम नहीं है। उनके अनुसार भारतवर्ष में वोटर्स की पहले से सख्या बढ गई किन्तु फिर भी वह अमेरली के लिये केवल ६ % ही है।

प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये वोट देने का अधिकार—हर एक प्रान्त में भिन्न भिन्न नियम हैं। १९१९ के अनुसार मार्गजनिक निर्वाचक मण्डल (General Constituency) के लिये प्रायः ये थे—(१) चुनाव के कम से कम १२ माह पत्रिये उस स्थान का निवासी हो और (२) कम से कम (अ) ३)† मालाना म्युनिसिपल टैक्स देना हो या (ब) ३६)

* बंगाल, विहार और उड़ीसा के मुसलमानों के लिये बहुत कम आमदनी रखी गई थी। पंजाब के मुसलमानों के लिये सबसे कम १०,०००) आमदनी पर टैक्स रखा गया।

† मध्यप्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में वार्षिक लगान या मालगुजारी ३०) से ५०) तक है।

चुनाव के लिये उम्मीदवार होने के लिये भी कुछ नियम हैं। उम्मेदवार का नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में अवश्य होना चाहिए* जहाँ से वह खड़ा रहा हो तथा उनकी उम्र २५ वर्ष से अधिक हो। इस स्थान पर १९३५ के एक्ट द्वारा चुनाव संबंधी होने वाले परिवर्तन का उल्लेख अनुचित न होगा।

ऊपर लिखा जा चुका है कि भारतीय फ़ेडरेशन स्थापित होने पर भी केन्द्र में दो व्यवस्थापिका सभायें रहेंगी। उस समय तक आधुनिक भारतीय व्यवस्थापिकाएँ ही कार्य करेंगी। भारतीय फ़ेडरेशन में सन् १९३५ के एक्ट के अनुसार 'काउंसिल आफ स्टेट' तथा 'फ़ेडरल असेंबली' स्थापित होंगी।

फ़ेडरल काउंसिल आफ स्टेट—उसमें ब्रिटिश भारत के १५६ प्रतिनिधि और दश ग़ियामना के अधिक से अधिक १०४ प्रतिनिधि रहेंगे। यह सब दो भागों में बँट कर प्रत्येक भाग का अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं रहता। विधान के अनुसार उसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्षों बाद

बंगाल—निवास संबंधी योग्यता के अतिरिक्त जो व्यक्ति पिछले वर्ष में कम से कम ४२) सालाना किराये वाले मकान का मालिक या किरायेदार हो; या जो इन्कम टैक्स देता हो; या जो सन् ३२ के बंगाल मोटर विहिकल एक्ट के अनुसार टैक्स देता हो; या जिसका नाम पिछले वर्ष के कलकत्ता कारपोरेशन के म्यूनिसिपल अमेसमेंट बुक अथवा लाइसेंस रजिस्टर या अन्य किसी रजिस्टर में दर्ज हो, कि उसने उस साल के लिये प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में कारपोरेशन को टैक्स या फ़ोत दी हो; या उसने पिछले वर्ष और उस साल के लिये कम से कम ॥) रोडसेस या ॥) चौकीदारी टैक्स या यूनियन टैक्स दिया हो, वह व्यक्ति वोटर होने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कम से कम फ़ाइनल मिडिल स्कूल पास कर चुका है, वह भी वोटर हो सकता है।

महिलाओं की योग्यता संबंधी नियम—सम्राट् के सेना विभाग के भूतपूर्व अफ़सर, नान कमीशन अफ़सर, या सैनिक की पेन्शन पाने वाली माता या विधवा वोटर हो सकती है। १५०) सालाना किराये के मकान की मालिक, या ३००) सालाना के किरायेदार या २४) सालाना म्यूनि-सिपल टैक्स देने वाले व्यक्ति की पत्नी को भी वोट देने का हक़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिस स्त्री ने मिडिल परीक्षा पास की है वह भी वोटर होने की अधिकारिणी है।

बिहार—निवास संबंधी योग्यता के अतिरिक्त जो व्यक्ति इन्कम टैक्स देता हो या १॥) म्यूनिसिपल टैक्स या ॥) चौकीदारी टैक्स देता हो वह सन्धल परगना के अतिरिक्त अन्य टेरिटोरियल सभ का वोटर हो सकता है। जमशेदपुर नोटिफ़ाइड एरिया के अन्दर जिसके पास २४) सालाना किराये की ज़मीन या मकान हो वह उस एरिया की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकता है। जो प्रान्त के अन्य स्थानों में ६) सालाना भाड़ा या ३) सालाना लोकल मेस देते हो या सन्धल परगना में ६) सालाना किराया

फ़ेडरल असेंबली में महिलाओं के लिये ९ सीटें सुरक्षित हैं। ब्रिटिश भारत की महिला प्रतिनिधियों के लिये महिलाओं का एक निर्वाचक संघ (Electoral College) स्थापित किया जायगा जिसमें प्रान्तीय असेंबली की महिला सदस्य होंगी। इस निर्वाचक संघ को ही महिला सदस्य चुनने का अधिकार होगा। नियमानुसार फ़ेडरल असेंबली में कम से कम दो मुस्लिम और एक ईसाई महिला का आना अनिवार्य है।

फ़ेडरल असेंबली के एंग्लोइंडियन, ईसाई, और यूरोपीयन प्रतिनिधियों के लिये भी क्रमशः निर्वाचक संघ होंगे जिनमें इन्हीं जातियों के प्रान्तीय असेंबली के सदस्य होंगे। वे ही नियमानुसार फ़ेडरल असेंबली के सदस्य चुनेंगे। वाणिज्य-व्यवसाय, ज़मींदार एवं मज़दूरों के लिये निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अनुसार उनका निर्वाचन होगा।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका तथा मताधिकार

ऊपर लिखा जा चुका है कि नवीन विधान के अनुसार मतदाताओं की संख्या लगभग ४ गुनी बढ़ जावेगी। आधुनिक काल में नागरिक के अधिकारों में शासन व्यवस्था के हेतु व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार महत्त्वपूर्ण है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका के आगामी चुनाव जो सन् ३७ के आरम्भ में होने वाले हैं नये विधान के अनुसार ही होंगे। अतएव मताधिकार का विषय विशेष महत्त्व रखता है। अतः मत देने की योग्यता संबंधी नियमों का उल्लेख करना आवश्यक है। नवीन विधान के अनुसार भी यद्यपि निर्वाचन एवं मताधिकार की योग्यता संबंधी नियम एक स नहीं हैं किन्तु फिर भी उनके आधार एवं सिद्धान्त एक ही हैं। नवीन विधान के अनुसार मर्दाने के आधार के अनिवार्य शिक्षा संबंधी योग्यता का भी अधिकार रखा गया है। नीचे कुछ मुख्य मुख्य प्रान्तों के मताधिकार एवं निर्वाचन संबंधी नियम दिए जाते हैं।

चौथा अध्याय

प्रबंधकार्य तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विषय

(Executive Govt. Central & Provincial Subjects.)

सन् १७७३ ईस्वी में ब्रिटिश पार्लमेंट ने ईस्टइंडिया कम्पनी के राज्य का शासन व्यवस्थित करने के अभिप्राय से 'रेग्युलेटिंग एक्ट' बनाया। इस समय भारतवर्ष में कम्पनी का राज्य बंबई, मद्रास तथा बंगाल प्रेसीडेंसियों में विभक्त था। प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में एक गवर्नर* था जो अपने प्रान्त का शासन अपनी कार्यकारिणी समिति की सहायता से ही किया करता था। रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ जिसके आधीन अन्य दो प्रेसीडेन्सियाँ भी कर दी गईं। इसकी सहायता के लिये ८ सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसका बहुमत मानने के लिये गवर्नर जनरल बाध्य था। यद्यपि बंगाल का गवर्नर समस्त भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किन्तु मद्रास तथा बंबई प्रेसीडेन्सी के भीतरी शासन प्रबंध का उत्तरदायित्व उसके ऊपर न था। सन् १७७३ ईस्वी में ही गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारिणी (Executive Council) का इतिहास आरम्भ होता है।

* प्रेसीडेन्सी गवर्नर की कार्यकारिणी में १०-१६ तक सदस्य होते थे। गवर्नर कार्यकारिणी का बहुमत मानने के लिये बाध्य था। शासन प्रबंध आदि हर एक विषय के लिये प्रेसीडेन्सी सरकार सीधे इंग्लैंड में कम्पनी के डायरेक्टर्स के ही निकट उत्तरदायी थीं।

सन् १७८४ ईस्वी में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटाकर ३ कर दी गई। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में गवर्नर जनरल तथा कार्यकारिणी में बहुधा मतभेद रहने के कारण राज्य संचालन में अनेको बाधाएँ आती थीं अतएव सन् १७८६ ईस्वी में गवर्नर जनरल को, घोर परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी के बहुमत की अवहेलना करने का अधिकार दे दिया गया। लगभग ५० वर्षों तक इसी प्रकार राज्य संचालन होता रहा। इन ५० वर्षों में पंजाब तथा निम्न के अतिरिक्त प्रायः समस्त भारत कंपनी के राज्य या उसकी संरक्षा में आ चुका था। इतने बड़े राज्य का सारा भार गवर्नर जनरल पर ही था। वही अपनी कार्यकारिणी की सहायता से, देश के लिए कानून बनाना तथा शासन प्रबंध किया करता था। सन् १८३३ के एक्ट के अनुसार केवल कानून बनाने में सहायता देने के लिए कार्यकारिणी समिति में एक और सदस्य नियत करने की व्यवस्था की गई। नियमानुसार यह कंपनी का नौकर नहीं हो सकता था। इस समिति ने कुछ विशेष लाभ न हुआ। अतएव सन् १८५३ में प्रबंधकार्य तथा कानून बनाने के कार्य पथक कर दिये गये।

सन् १७८४ ईस्वी में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटाकर ३ कर दी गई। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में गवर्नर जनरल तथा कार्यकारिणी में बहुधा मतभेद रहने के कारण राज्य संचालन में अनेकों बाधाएँ आती थीं अतएव सन् १७८६ ईस्वी में गवर्नर जनरल को, घोर परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी के बहुमत की अवहेलना करने का अधिकार दे दिया गया। लगभग ५० वर्षों तक इसी प्रकार राज्य संचालन होता रहा। इन ५० वर्षों में पंजाब तथा सिन्ध के अतिरिक्त प्रायः समस्त भारत कंपनी के राज्य या उनकी नरक्षा में आ चुका था। इतने बड़े राज्य का सारा भार गवर्नर जनरल पर ही था। वही अपनी कार्यकारिणी की सहायता से, देश के लिए क़ानून बनाता तथा शासन प्रबंध किया करता था। सन् १८३३ के एक्ट के अनुसार केवल क़ानून बनाने में सहायता देने के लिए कार्यकारिणी समिति में एक और सदस्य नियत करने की व्यवस्था की गई। नियमानुसार यह कंपनी का नौकर नहीं हो सकता था। इस सुधार से कुछ विशेष लाभ न हुआ। अतएव सन् १८५३ में प्रबंधकार्य तथा क़ानून बनाने के कार्य पृथक् कर दिये गये एवं कार्यकारिणी के चौथे सदस्य को समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने तथा वोट देने का अधिकार देकर, उसे पूर्ण सदस्य बना लिया। सन् १८३३ के एक्ट के अनुसार प्रेसीडेन्सी गवर्नर तथा कार्यकारिणी में क़ानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। अतएव अब सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत का राज्य-संचालन वाइस्-रॉय सहित गवर्नर जनरल के ही हाथ में आ गया। इस प्रबंध से भी सत्तोप-जनक परिणाम न हुआ, अतः सन् १८६१ में पुनः वाइस्-रॉय एक्ट पारित हुआ जिसने प्रेसीडेन्सी सरकारों को प्रान्तीय विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार जापित कर दिया गया और गवर्नर जनरल की वाइस्-रॉय के सदस्यों की संख्या ५ कर दी गई। इस पांच सदस्यों में से कम से कम ३ ऐसे हों गये जिन्हें भारत सरकार की सीटरी करने का मंत्र १० वर्ष

27

दस से अधिक न होगी। इनके चुनाव करने और हटा देने का अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा। प्रत्येक मंत्री को व्यवस्थापिका सभा का सदस्य होना आवश्यक होगा। यदि कोई मंत्री नियुक्त करने से छ महीने तक व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न हो सके तो उसे अपना पद त्याग देना पड़ेगा। साधारणतः गवर्नर जनरल का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रियों की राय के अनुसार काम करे किन्तु विशेष स्थिति आने पर वह चाहे तो मंत्रियों की राय न माने और अपनी राय के अनुकूल चले। गवर्नर जनरल को आदेश है कि जहाँ तक हो सके वह मंत्रियों और सचिवों (Counsellors) की संयुक्त राय लेकर काम किया करे।

मन् १९१९ के एक्ट के अनुसार मन् १९२१ में कार्य शुरू हुआ। एक्ट के अनुसार मद्रास, बंबई तथा बंगाल प्रान्त में ४ सदस्य हैं। इनमें दो हिन्दुस्थानी तथा २ यूरोपियन हैं। अन्य प्रान्तों में प्रान्तीय कार्य-कारिणी समिति २ सदस्य हैं। प्रथा के अनुसार इन प्रान्तों में भी एक हिन्दुस्थानी तथा एक यूरोपियन सदस्य हैं। केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में एक ही सदस्य की कार्यकारिणी है। एक्ट के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्य में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना अनिवार्य है जो भारत सरकार की नोकरी में कम से कम १२ वर्ष रहा हो। कार्यकारिणी के सदस्य साधारण तौर पर ५ वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। इस समिति का हर एक सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापिका का सरकार का सदस्य होता है।

प्रान्त का कार्यकारिणी का ब्रह्मका में गवर्नर है अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता है। यदि किसी प्रान्त का कार्यकारिणी समिति में मतभेद हो तो साधारण तौर पर ब्रह्मका का ही वाद हो जाता है। कार्यकारिणी के समान उसका भी समान जतरायवत (Joint Responsibility) है। व्यवस्थापिका सभा केवल इनके साथ ही आदान

सर्वप्रधान है। अन्य कर्मचारी प्रान्त के शासन संबंध में सदैव उसकी जानकारी कराते रहते हैं। वह दोनों ओर (मंत्री और कार्यकारिणी) के गुप्त से गुप्त मामलों से भिन्न रहता है। गवर्नर स्वयं बड़ा नीतिज्ञ, दूरदर्शी तथा विद्वान होता है। अतएव यद्यपि शासन कार्य कार्यकारिणी के सदस्य और मंत्री ही सँभालते हैं तथापि वास्तविक शासन संचालन में गवर्नर का बहुत प्रभाव पड़ता है। सन् १९३५ के एक्ट में भी काउन्सिल आफ़ मिनिस्टर्स और गवर्नर के सम्बन्ध में उपर्युक्त सिद्धान्त प्रचलित रहेगा। विशेष परिस्थिति अथवा आवश्यकता आ जाने पर गवर्नर अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने और प्रवन्ध करने का अधिकारी रहेगा। सूबे के उन विभागों का शासन जो पिछड़े हुए निश्चिन्त किये जायेंगे (Back ward area) गवर्नर बिना मंत्रियों के परामर्श किये स्वयं करेगा।

मद्रास प्रान्त को छोड़कर अन्य प्रान्तों के शासन की सुविधा के लिए विभाग कर दिये गये हैं जिन्हें कमिश्नरी कहते हैं। कमिश्नरी का प्रधान कर्मचारी कमिश्नर है। कमिश्नर का कार्य जिला तथा जिले का शासन प्रबंध डिवीजन के जिलों के प्रबंध का निरीक्षण करना तथा डिवीजन के मध्य में प्रान्तीय सरकार को रिपोर्ट करना है। प्रत्येक डिवीजन अर्थात् कमिश्नरी में जिले हैं जिनका प्रधान कर्मचारी या जिलार्थीश डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर कहलाता है।

कलेक्टर शब्द का प्रयोग वारन ऑफ़िसर के समय में भी था। उस समय अपनी का बगाल की दावाना का प्रबंध करने के लिए प्रान्त को छोट छोट हिस्स में बांटना पड़ा था। प्रत्येक हिस्स में लगान वसूल करने के लिए करने का एक प्रधान कर्मचारी था जिस कलेक्टर कहते थे। उसी समय में कलेक्टर का प्रधान सचिव लगान सचिवों का है। धीरे धीरे कलेक्टर के सचिव का सरवा बढ़ता गइ और इसा कम में उसका अधिकारों की भी बढि होना गइ।

जिले का शासन प्रबंध कई विभागों द्वारा होता है। प्रत्येक विभाग

पाँचवाँ अध्याय

गवर्नमेन्ट का आय-व्यय और बजट

सन् १८३३ में आर्थिक नियंत्रण, केन्द्रिक शासन (Central Government) के अधिकार में चला गया। उस समय में प्रायः जितनी आमदनी होती थी वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के ही कण्ठ में जमा होती थी और उसके खर्च करने का अधिकार भी उसी के हाथ में था। यदि सूबों की सरकारों को कोई आवश्यकता पड़ी तो वे केन्द्रिक शासन से मांगने थे। सूबों की सरकारों के हाथ में केवल कुछ कर (Cess) वसूल करने और निश्चित विषयों पर खर्च करने का अधिकार रह गया था।

केन्द्रिक सरकार की आर्थिक परिस्थिति इनके पर भी अनेक कारणों से अच्छी न रही। उसका प्रबन्ध संतोष-जनक न था और फौज पर खर्च भी बढ़ता जाता था। कई बार लड़ाइयाँ भी छिड़ती रहीं। परिणाम यह हुआ कि १८५७ तक सरकार के ऊपर कुल मिलाकर साठ करोड़ रुपये का कर्ज लद गया। सन् १८६० तक आमदनी का आधा हिस्सा पुलिस और फौज पर ही खर्च हो जाता था। नमक, आयात-निर्यात और स्टाम्प पर कर बढ़ाने पर भी कुछ काम न बना। अतएव इस समस्या के सुलझाने के लिए जेम्स ब्रिन्सन साहब सन् १८६० में विलायत से अर्थ सचिव (Finance Minister) बनाकर भेजे गये। उन्हीं के समय से आधुनिक आर्थिक संगठन और सुधार का आरम्भ होता है। उनके समय के पहले सरकार की आमदनी के, मालगुजारी (Land Revenue)

पाँचवाँ अध्याय

गवर्नमेन्ट का आय-व्यय और बजट

सन् १८३३ से आर्थिक नियंत्रण, केन्द्रिक शासन (Central Government) के अधिकार में चला गया। उस समय से प्रायः जितनी आमदनी होती थी वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया के ही फण्ड में जमा होती थी और उसके खर्च करने का अधिकार भी उसी के हाथ में था। यदि सूबों की सरकारों को कोई आवश्यकता पड़ती तो वे केन्द्रिक शासन से माँगते थे। सूबों की सरकारों के हाथ में केवल कुछ कर (Cess) वसूल करने और निर्दिष्ट विषयों पर खर्च करने का अधिकार रह गया था।

केन्द्रिक सरकार की आर्थिक परिस्थिति इनके पर भी अनेक कारणों से अच्छी न रही। उसका प्रबंध संतोष-जनक न था और फौज पर खर्च भी बढ़ता जाता था। कई बार लड़ाइयाँ भी छिड़ती रहीं। परिणाम यह हुआ कि १८५७ तक सरकार के ऊपर कुल मिलाकर साठ करोड़ रुपये का कर्ज लद गया। सन् १८६० तक आमदनी का आधा हिस्सा पुलिस और फौज पर ही खर्च हो जाता था। नमक, आयात-निर्यात और स्टाम्प पर कर बढ़ाने पर भी कुछ काम न बना। अतएव इस समस्या के सुलझाने के लिए जेम्स विल्सन साहब सन् १८६० में विलायत से अर्थ सचिव (Finance Minister) बनाकर भेजे गये। उन्हीं के समय से आधुनिक आर्थिक संगठन और सुधार का आरम्भ होता है। उनके समय के पहले सरकार की आमदनी के, मालगुजारी (Land Revenue),

डाकखाना और तार—डाकखाने का आरम्भ सन् १८३७ से हुआ किन्तु सन् १८५४ में उसकी वातायदा वृद्धि होने लगी। सन् १८५५ में तार का भी आरम्भ हुआ और तब से बराबर उन्नति होती रही। किन्तु इन विभागों में खर्च बढ़ता गया और लाभ के बदले नुकसान ही अधिक होता रहा। इन दोनों में सन् १९०२-३ में सिर्फ ५ लाख का फायदा हुआ। सन् १९३३-३४ में इनमें ५ लाख के लगभग घाटा हुआ। किन्तु इनकी वृद्धि होती रही जिसमें देश को आर्थिक और अन्य प्रकार के अनेक लाभ हुए। अतएव इनके घाटे से इनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुमान नहीं किया जा सकता। तथापि नकद फायदे की दृष्टि से इन विभागों पर अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नगण्य हैं।

रेल—रेल का आरम्भ सन् १८४५ में हुआ। चूँकि रेलों के निकालने में खर्च बहुत पड़ता और सरकार के पास धन की कमी थी अतएव उसने विलायत की कम्पनियों को ठेका दे दिया कि वे अपना धन लगा कर, जिस पर सरकार उनको ५) सैकड़ा मूद देगी, रेलें खोले। सरकार ने जमीन मुफ्त में दी। रेलों में पहले यथेष्ट लाभ न हुआ अतएव आय-व्यय पर गहरा निरीक्षण करने पर भी मूद की कमी पूरी करने के लिए सरकार को भारी रकम अपनी गाँठ से देनी पड़नी थी। सन् १८७० से सरकार को स्वयं अपनी रेलें निकालने की मूर्झी। इसके लिए भी पहले कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी। किन्तु उन्नति बड़ी ही मुश्त दिखाई पड़ी इसलिए सन् १८७९ में सरकार ने मस्थानों के साथ माझा करके रेलें खुलवाने की प्रथा निकाली। सन् १८८९ में सरकार ने अधिक प्रयत्न करने की चेष्टा की। इसके अलावा पुरानी कम्पनी का ठेका खतम होने पर सरकार ने उनको स्वयं अपने अधिकार में लेने की नीति निकाली। (सन् १९३०) तक ४०,००० हजार मील तक रेल की सड़के फैल गयीं। और जितनी पुरानी ठेकेवाली कम्पनियाँ थी वे सरकार के अधिकार में हो गई। इस समय भारत सरकार का संगठन समार के सबसे बड़े रेलवे संगठनों में

शस्त्रों में परिवर्तनों के कारण सफलता न हुई। उलटे खर्च बढ़ता गया। सन् १८७६ में १७ करोड़ ४० लाख से, १९०४ में ३० करोड़ २० लाख और यूरोपीय महायुद्ध के कारण ६६ करोड़ हो गया। बड़े प्रयत्न करने से सन् १९३० में ५५ करोड़ और अब लगभग ५० करोड़ है।^१

कर्ज का सूद—ऊपर लिखा जा चुका है कि १८६० में सरकार पर ६० करोड़ कर्ज था। युद्धों के कारण एवं रेलों, नहरों आदि के निकालने के कारण यह कर्ज बढ़ते बढ़ते सन् १९२९ तक १०७४ करोड़ तथा १९३५ तक १२३५^१/_२ करोड़ हो गया। इसमें से १७१ करोड़ तो ऐसे हैं जिन पर सूद देने के सिवा किसी भी लाभ या हित का साधन नहीं होता। सारांश यह कि भारत की सरकार को वारह करोड़ चौदह लाख रुपया केवल सूद में ही देना पड़ता है। इस कर्ज से उद्भूत होने के कोई लक्षण अभी तक दिखायी नहीं पड़ते।

शासन का अन्य खर्च—केन्द्रिक सरकार पाँच छोटे सूबों का प्रबन्ध करती है। ये हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त^२, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर-मारवाड़, देहली सूबा और अन्दमन द्वीप। इसके अलावा राजनैतिक विभाग (Foreign and Political Departments), खोज (Research), संचर (Civil Aviation) और वायुमण्डल विभाग (Meteorology), आदि अनेक विभाग उसके जिम्मे हैं। इन सब पर सन् १९३४-३५ में १२^३/_४ करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। इनके अलावा पेन्शनो और मालगुजारी बसूल करने के प्रबन्ध पर भी सन् १९३० में ११ करोड़ १५ लाख खर्च हुआ।

^१ इसका विस्तृत वर्णन मेना विभाग के अध्याय में देखिए।

^२ अब अलाहदा सूबा हो गया है। किन्तु इसका खर्च इसकी आमदनी से पूरा नहीं होता अतएव भारत की सरकार को कमी पूरी करनी पड़ती है।

जम्मा में परिवर्तनों के कारण सफलता न हुई। उल्टे खर्च बढ़ता गया। सन् १८७३ में १७ करोड़ ४० लाख में, १९०४ में ३० करोड़ २० लाख और यूरोपीय महायुद्ध के कारण ६६ करोड़ हो गया। बड़े प्रयत्न करने में सन् १९३० में ५५ करोड़ और अब लगभग ५० करोड़ है।^१

कर्ज का सूद—ऊपर लिखा जा चुका है कि १८६० में सरकार पर ६० करोड़ कर्ज था। युद्धों के कारण एवं रेलों, नहरों आदि के निकालने के कारण यह कर्ज बढ़ने बढ़ने सन् १९२९ तक १०७४ करोड़ तथा १९३५ तक १०३५^१ करोड़ हो गया। इसमें से १७१ करोड़ तो ऐसे हैं जिन पर सूद देने के सिवा किसी भी लाभ या हित का साधन नहीं होता। सारांश यह कि भारत की सरकार को वार्षिक करोड़ चौदह लाख रुपया केवल सूद में ही देना पड़ता है। इस कर्ज में उद्भूत होने के कोई लक्षण अभी तक दिखायी नहीं पड़ने।

शासन का अन्य खर्च—केन्द्रिक सरकार पांच छोटे सुबों का प्रबन्ध करती है। ये हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त^२, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर-मारवाड़, देहली सूबा और अन्धमन द्वीप। इसके अलावा राजनैतिक विभाग (Foreign and Political Departments), खोज (Research), खेचर (Civil Aviation) और वायुमण्डल विभाग (Meteorology), आदि अनेक विभाग उसके जिम्मे हैं। इन सब पर सन् १९३४-३५ में १०^१ करोड़ रुपये में अधिक खर्च हुआ। इनके अलावा पेन्शन और मालगुजारी वसूल करने के प्रबन्ध पर भी सन् १९३० में ११ करोड़ १५ लाख खर्च हुआ।

^१ इसका विस्तृत वर्णन सेना विभाग के अध्याय में देखिए।

^२ अब अलाहदा सूबा हो गया है। किन्तु इसका खर्च इसकी आमदनी से पूरा नहीं होता अतएव भारत की सरकार को कमी पूरी करनी पड़ती है।



बनाई गई। उस सेना की संख्या ३३,००० रही गई, और उसमें केवल अंग्रेजों को ही भरती करने का निश्चय बनाया गया। जो अंग्रेज उसमें भरती होने हैं उन्हें निपामानुसार अवसर पड़ने पर लड़ाई पर जाने के लिए तैयार रखा जाता है। इसकी शिक्षा उमर के अनुसार ही निर्धारित की जाती है और स्थानीय होती है। हर एक साल में इसके लिए जंगल जंगल पर प्रबंध किया गया है।

अनुपूर्वी सेना में सेना के हर एक विभाग की शिक्षा देने का, अंग्रेज—भुट्टमवार, तोपखाना, इंजीनियरिंग, डेरीकार्म, मेसिनर, मिगनल आदि—का प्रबंध किया गया है। इस सेना का प्रत्येक भाग उस स्थान के व्यवस्थित सेना-विभाग के अन्तर्गत है। इसकी शिक्षा साल भर समय समय पर होती रहती है और प्रतिदिन के हिमाय में उन्हें कुछ वेतन भी मिलता है। इस सेना में भरती होने की कोई निश्चित अवधि नहीं है किन्तु फिर भी ४ वर्ष के बाद या ४५ वर्ष की उमर हो जाने पर उसे उच्छानुसार छोड़ देने की इजाजत है।

इंडियन टेरिटोरियल फोर्स—सेना में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के अभिप्राय में ही उसका निर्माण किया गया है। उसे भारतीय सेना का एक अंग बना दिया गया है और उसी में से व्यवस्थित सेना के लिए भरती की जाती है। इसका मुख्य कर्तव्य देशरक्षा ही है। यह बताया जा चुका है कि यूरोपीय महायुद्ध के समय में देशरक्षा के अभिप्राय में स्वयंसेवकों का दल बनाया गया था। यह सेना उसी दल का नवीन संगठन, इंग्लैंड के पुराने मिलिशिया के आधार पर है।

इंडियन टेरिटोरियल फोर्स में आजकल १८ प्रांतीय बेटेलियन, ३ शहरों की यूनिट (Urban Units), ११ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर और एक मेडिकल ब्रांच है। प्रांतीय बेटेलियन का अभिप्राय उसे व्यवस्थित सेना के ही रूप में लाना है। अनएव इसकी जिम्मेदारी अधिक है। आवश्यकता पड़ने पर इसी में से व्यवस्थित सेना में सैनिक लिये जायेंगे।

ही में पहली जून १९३५ को क्वेटा में भयंकर भूचाल आया जिसमें हजारों व्यक्ति मरे एवं घायल हुए। इस अवसर पर भी हवाई जहाजों ने अनुपम एवं प्रशंसनीय सेवा की है।

इंडियन एयर फ़ोर्स—सेना के अन्य विभागों की तरह हवाई जहाज के विभाग में भी भारतीयों को स्थान मिलने लगा है। सरकार के द्वारा ८ अक्टूबर सन् १९३२ में इंडियन एयर फ़ोर्स भी स्थापित कर दिया गया है। क्रेनवेल के कालेज में भारतवासियों के लिए भी संख्या निश्चित हो गई है। आशा की जाती है कि कुछ वर्षों के बाद 'इंडियन एयर फ़ोर्स' अच्छी उन्नति कर लेगा।

सेना विभाग का शासन प्रबंध—काउंसिल सहित गवर्नर जनरल ही सेना विभाग के शासन प्रबंध का अन्य विभागों के समान प्रधान है। किंतु सेना के संचालन एवं नीति नियंत्रण का सारा भार कमांडर-इन-चीफ़ के ही हाथों में है। कमांडर-इन-चीफ़ अर्थात् भारतीय सेना का प्रधान सेनापति वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य और अपने विभाग का प्रधान है। इसके आधीन थलसेना, जलसेना, वायुसेना आदि सब विभाग हैं। सेना संबंधी नीति आदि के लिये प्रधान सेनापति का अब सीधे इंग्लैंड के युद्ध विभाग (War Office) से ही संबंध है।

प्रधान सेनापतिके परामर्श और सहायता के लिये ४ सदस्यों की एक छोटी सी समिति है। इसका सभापति स्वयं प्रधान सेनापति है तथा क्वार्टर मास्टर जनरल, मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस, मेना विभाग का भारत सरकार का सेक्रेटरी (Secretary of the Government of India in the Army Department) और सेना संबंधी धन का अर्थ मंत्री (Financial Adviser of Military Finance) इसके सदस्य हैं।

सेना खर्च (Army Expenditure)—यूरोपीय महायुद्ध के पहिले (१९१३-१४) सेना विभाग पर २९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होते थे।

विभाग', दूसरे को 'एडजुटेंट जनरल विभाग', तीसरे को 'क्वार्टर मास्टर जनरल' तथा चौथे को 'मास्टर जनरल आफ आर्डियेस विभाग' कहते हैं। पहिले विभाग के काम मेना की नीति निश्चित करना, देश-रक्षा के लिये उचित स्थानों पर मेना की नियुक्ति और सैनिक शिक्षा का प्रबंध आदि करना है। दूसरे विभाग के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती करना, आक्रमणों की नियुक्ति, मेना की तबदीली, उमकी व्यवस्था, सैनिक निकटियों का प्रबंध करना आदि है। तीसरे विभाग का कार्य रसद आदि पहुँचाना है। चौथा विभाग वस्त्र, साजसामान, भोजन की सामग्री, अस्त्रशस्त्र आदि युद्ध की सामग्री का प्रबंध करना है। इनके अनिरिक्त और भी छोटे विभाग तथा अफसर हैं जिनमें इंजीनियर उन चीफ सैनिक सेक्टरी विशेष उल्लेखनीय है।

निम्नांकित नक्शे में सैनिक शासन की श्रृंखला स्पष्ट हो जावेगी—

आठवाँ अध्याय

शान्ति और न्याय

पुलिस

अंग्रेजी राज्य के पहले अर्थात् मुसलमानी काल में पुलिस का काम तीन हिस्सों में बँटा हुआ था। शहरों विशेषतः बड़े शहरों का प्रबंध कोतवाल के हाथ में था। उसकी सहायता के लिए मिपाही होते थे। शहर के बाहर बड़ी सड़कों आदि का प्रबन्ध फौजदारों के हाथ में था। सड़कों और रास्तों पर शान्ति रखना उसके कर्तव्यों में था। सरकार* में शान्ति रखने का भार अमल गुजार पर रहता था। उसके निरीक्षण में गाँवों में पुलिस का काम मुकद्दम और चौकीदार करने थे। इस प्रबन्ध में सूत्रों की परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण कुछ हर हर भी कर दिया जाता था। इन साधनों के अलावा गुप्त चर अर्थात् खुफिया पुलिस भी रहती थी जो प्रायः केन्द्रिक शासन के निरीक्षण में थी। मुगल साम्राज्य के जीर्णोद्धार हो जाने पर उनका पुलिस प्रबन्ध भी बिगड़ गया। यद्यपि पुराने नाम के पदाधिकारी थे किन्तु शायद गाँव के चौकीदार का छान कर रख कर कर्तव्य विमुक्त हो नहीं किन्तु श्रमोन्माद करन लग गे। जमींदारों के हाथ में अधिक शक्ति चली गई और वे और सामा के गाँव पुलिस के काम भी स्पेच्छानुसार करन लग।

* सूत्रों का भाग जो कमिश्नरी अथवा जिले की तरह होता था।

हैं किन्तु जिले की पुलिस के संगठन आदि विषयों में यह अपने में ऊपर पुलिस विभाग के अफसरों का मानवत है। जिला के एस० पी० की सहायता के लिये बड़े शहरों में एक अमिस्टेन्ट एस० पी० (A.S.P.) भी रखा जाता है। किन्तु साधारणतः एस० पी० के नीचे डिप्टी-सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस होते हैं जो प्रायः हिन्दुस्तानी होते हैं। ये लोग जिले के एक हिस्से के प्रबन्धक होते हैं और अपने हल्के में दौरा करके निरीक्षण करती हैं। प्रत्येक हल्के में कई थाने होते हैं। थाने का अफसर थानेदार होता है। थानेदार की सहायता के लिए नायब, दीवान, कान्गडेवल, चौकीदार आदि रहते हैं। थाने के अन्दर कई पुलिस की चौकियाँ होती हैं जिनमें डेपू कान्गडेवल और कई कान्गडेवल रहते हैं। गाँवों में पुलिस चौकीदार रहते हैं। इस प्रकार शहरों में लेकर गाँव तक पुलिस का जाल फैला हुआ है।

इस सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये कि प्रसीडेन्सी डाइरम्स (कलकत्ता, नागपुर, मद्रास) का पुलिस प्रबन्ध मध्य की साधारण पुलिस के संगठन से भिन्न है। वहीं वह इन्स्पेक्टर जनरल और पुलिस के द्वारा नियंत्रित किया होता है। इन शहरों की पुलिस का संगठन भी कुछ भिन्न है।

कार बढ़ाकर उसकी उपाधि District and Sessions Judge कर दी। इसी प्रकार हिन्दुस्थानी कमिश्नर को मुख्य सदर अमीन (Principal Sadar Amin) की उपाधि दी। ये ही आगे चलकर सन् १८६८ में Subordinate Judge कहलाये। इनका पद District and Sessions जज के नीचे होता है। छोटे मामलों को तय करने वाली Court of Requests सन् १८५० में Small Cause Courts के नाम से संगठित कर दी गई।

मद्रास में १८०१ में और बम्बई में १८२३ में मेयर कोर्ट के बदले सुप्रीमकोर्ट बनी। सन् १८६५ में दोनों सूबों में भी हाईकोर्ट और १८६६ में इलाहाबाद में हाईकोर्ट कायम हो गये। बाद को अन्य सूबों में जो* हाईकोर्ट बने हैं वे सन् १८६१ के पार्लिमेंट के एक्ट के ही आधार पर हैं। इसके बाद पार्लिमेंट द्वारा नहीं किन्तु गवर्नर जनरल की काउन्सिल द्वारा चीफ कोर्ट और जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट की स्थापना भिन्न भिन्न समय में अन्य सूबों में की गई। सन् १८६५ से १८७५ के बीच में सब जगह दीवानी अदालतें एक ही ढंग की कर दी गईं।

सन् १९३५ के एक्ट के अनुसार जब भारतमें फ़ेडरेशन स्थापित होगा तब देहली में फ़ेडरल कोर्ट (Federal Court) नामक एक ऐसी अदालत बनाई जायगी जो फ़ेडरेशन सम्बन्धी कानूनी मामलों अथवा सूबों और रियासतों के पारस्परिक या केन्द्रिक शासन के झगड़ों का निर्णय करे। इसमें एक चीफ़ जस्टिस आबू इण्डिया और छः जज होंगे। जिनकी नियुक्ति सम्राट् करेंगे। इस अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध कुछ शर्तों पर इंग्लैंड की प्रिवी काउन्सिल में अपील की जा सकेगी।

* पटना का हाईकोर्ट सन् १९१६ में, लाहौर का १९१९ में और नागपुर का १९३६ में बना।

गये। इसी काल में (१७९३) फ़ौजदारी के क़ानूनों का भी प्रथम संस्कार किया गया।

लार्ड वेलज़ली के समय में कलकत्ते की निज़ामत अदालत में गवर्नर जनरल और उसकी काउन्सिल के सदस्यों के वजाय तीन अंग्रेज़ जज नियुक्त कर दिये गये। अन्त में सन् १८६२ में यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर हाईकोर्ट के रूप में आ गई।

संगठन

गाँवों में मुकद्दम अथवा पंचायत दीवानी अधिकार के साथ ही फ़ौजदारी अधिकार रखती है। मद्रास में जहाँ ये संस्थाएँ पूरी तरह विकसित हैं ये छोटे झगड़े आदि का फ़ैसला करती हैं। वह थोड़ा जुर्माना एवं कुछ घंटों के लिए कैद भी कर सकती है। सी०पी० में डिस्ट्रिक्ट बेंच को १० से २० तक जुर्माना करने का अधिकार है। सन् १९२८ में १३९२ मुकद्दम और २३२६ पंचायतें भारत में फ़ौजदारी अधिकार रखते थे।

गाँवों से ऊपर तहसीलों में नायब तहसीलदार और तहसीलदार को भी फ़ौजदारी के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। प्रायः तहसीलदार दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार रखता है। नगरों में अवनैतिक मजिस्ट्रेट भी रखा दिये जाते हैं जो फ़ौजदारी के मुकद्दमे करते हैं।

तहसीलों के ऊपर जिले के एक विभाग का अफसर होता है जो गवर्नरिज्मन्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। उनको प्रायः प्रथम दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं अर्थात् ये १००० जुर्माना और दो वर्ष तक की कैद कर सकते हैं।

उपर्युक्त फ़ौजदारी के अफसर जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर) की अध्यक्षता और निरीक्षण में रहते हैं। यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट का फ़ौजदारी का पूरा अधिकार है किन्तु अनेक कामों में पति रहते

नवाँ अध्याय

जनोपयोगी विभाग—कृषि, शिक्षा, पब्लिक
वर्क्स तथा सिंचाई, सफाई एवं आवकारी

Departments of Public Utility—Agriculture,
Public Works Dept., Irrigation, Sanitation,
Excise & Education.

कृषि-विभाग

हमारा देश कृषि प्रधान है। प्राचीन काल से ही शासक कृषि की ओर विशेष रूप से ध्यान देते चले आये हैं। भूमि कर ही शासकों की आमदनी का प्रधान साधन रहा है। वर्षा कम अथवा अधिक होने के कारण देश में भयंकर दुर्भिक्ष की सदैव ही आशंका बनी रहती है। प्राचीन काल में आवा-गमन के साधनों का अभाव होने के कारण तथा सिंचाई की विशेष सुविधा न होने से दुर्भिक्ष बड़े भयंकर होते थे। दूरी के कारण दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को समय पर सहायता पहुँचाना असाध्य हो जाता था। इसके अतिरिक्त देश में वैज्ञानिक ढंग से खेती बारी न होने के कारण उपज में भी विशेष वृद्धि नहीं हो सकी। सन् ५७ के विद्रोह के कारण देश में बड़ी अशान्ति फैली जिससे खेती बारी में अनेकों बाधाएँ उपस्थित होने लगीं। प्रजा की सुविधा के विचार से लार्ड केनिंग ने काश्तकारी एक्ट के अनुसार बंगाल, बिहार, यू० पी० और मी० पी० के किसानों के अधिकार निश्चित कर उनकी बहुत सी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न किया।

इंस्टीट्यूट तथा कृषि विज्ञान के कालेजों को धन से तथा परामर्श से सहायता पहुँचानी है। इस काउन्सिल का कृषि विज्ञान संबंधी हर एक समस्या से एक सा ही व्यवहार है; चाहे वह समस्या सरकारी या गैर सरकारी या देशी गिर्यामनों की ही क्यों न हो। प्रांत की तथा देशी गिर्यामनों की समस्याएँ इन काउन्सिल के पास प्रांतीय सरकारों या गिर्यामनों के द्वारा अपनी योजना (स्कीम) भेजनी हैं। एडवाइजरी बोर्ड उन पर विचार कर काउन्सिल की प्रबंधकारिणी के पास अपनी मित्राणि भेजता है। यदि योजना उचित तथा लाभदायक समझी गई तो सरकारी कोष से संस्था को आर्थिक सहायता मिलती है।

कृषि संबंधी अनेक विषय हैं। अतएव उन पर विचार करने तथा कृषि की उत्पत्ति एवं समस्याओं की जाँच करने के लिए काउन्सिल ने कमेटियाँ बना रखी हैं। आजकल ऐसी ८ कमेटियाँ हैं जिनमें शक्कर कमिटी (Sugar Committee), फर्टिलाइजर कमिटी (Fertilisers Committee), लोकस्ट कमिटी (Locust Committee), ऑइल क्रशिंग (Oil Crushing) इंडस्ट्रियल कमिटी (Industrial Committee) तथा कैटल ब्रीडिंग कमिटी (Cattle breeding Committee) मुख्य हैं। इनके अलावा समय समय पर अन्य नव-कमेटियाँ भी आवश्यकतानुसार बना ली जाती हैं।

भारतीय व्यवस्थापिका सभा काउन्सिल के बजट के अतिरिक्त २५ लाख रुपया मलाना तथा वैज्ञानिक खोज के लिए ५ लाख रुपया मलाना और देती है। काउन्सिल देश की कृषि समस्याओं में ऐक्य बढ़ाकर कृषि की उत्पत्ति का प्रयत्न करती है। इसके कार्यों को देखकर आगा की जाती है कि यह कुछ ही वर्षों में कृषि तथा गरीब किसानों की उत्पत्ति में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगी।

प्रान्तीय कृषि विभाग—सन् १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तीय कृषि विभाग मंत्री के आधीन है। इसका प्रधान अफसर डायरेक्टर आफ

विभाग के अंतर्गत स्कूलों का निरीक्षण इंस्पेक्टर करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर डायरेक्टर के पास भेजा करते हैं। इनका कार्य डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यों का भी निरीक्षण करना है। ज़िले के स्कूलों की देख रेख डिप्टी इंस्पेक्टर करते हैं। ये इंस्पेक्टर को स्कूलों के संबंध की रिपोर्ट भेजा करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड के स्कूलों का भी निरीक्षण ये करते हैं।

शिक्षा विभाग के उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक और कर्मचारी होता है जिसे सेक्रेटरी हाई स्कूल बोर्ड या सेक्रेटरी हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडिएट बोर्ड कहते हैं। इसका प्रधान कार्य परीक्षा एवं पाठ्य विषयों तथा पुस्तकों को निर्धारित करना है। इनकी सहायता के लिए अनेक कर्मचारी होते हैं। पाठ्य पुस्तकों तथा विषयों के निर्धारित करने के लिए छोटी बड़ी अनेको कमेटियाँ हैं।

विश्वविद्यालय का प्रमुख पदाधिकारी वाइस चांसलर कहलाता है जो प्रबंध कारिणी (Executive Council or Senate) के कानून प्रस्ताव आदि के अनुसार मंस्था का नियंत्रण करता है। वाइस चांसलर वैतनिक या अवैतनिक होते हैं। इन्हें कही तो सरकार नियुक्त करती है और कही इनका चुनाव होता है। वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर होता है जो प्रायः प्रान्त का गवर्नर ही रहता है। किसी किसी विश्वविद्यालय के—जैसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी—चांसलर राजा महाराजा या धनीमानी व्यक्ति भी होते हैं। विश्वविद्यालय का प्रबंध करने के लिए एक समिति होती है जिसे प्रबंधकारिणी समिति (Executive Council or Senate) कहते हैं। इसका सभापति वाइस चांसलर ही होता है। परीक्षा, दफ्तर के कार्य तथा अन्य प्रकार की देख भाल 'रजिस्ट्रार' करता है। उच्चशिक्षा कई अङ्गों में विभक्त की गई है—जैसे आर्ट्स, विज्ञान, कानून, मेडिसिन इत्यादि। प्रत्येक अङ्ग का एक एक अधिपति होता है—जो उस के

विभाग न था। मिलिटरी बोर्ड का कार्य क्षेत्र केवल सेना संबंधी ही था। पंजाब में नहरों आदि का कार्य पहले से ही हो रहा था अतः पंजाब विजय के उपरान्त सन् १८४९ में पंजाब प्रान्त में पब्लिक वर्क्स विभाग व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया जिसके प्रधान इंजीनियर लेफ्टनेंट कर्नल नेपियर नियुक्त हुए। इस समय सेना संबंधी इमारत, सड़कें आदि के सिवा अन्य सड़कें, सरकारी इमारत तथा सिंचाई के साधन आदि की आवश्यकता की ओर भी कंपनी का ध्यान आकृष्ट हो रहा था। देश में रेल, तार आदि का भी आयोजन करने का प्रयत्न किया जा रहा था। अतः सन् १८५० में सरकार ने पब्लिक वर्क्स के लिए एक जांच कमीशन नियुक्त किया।

इस कमीशन ने मिलिटरी बोर्ड के स्थान पर प्रान्तीय सरकार के नियंत्रण में ही मिविल तथा मिलिटरी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए एक ही पब्लिक वर्क्स विभाग खोलने का प्रस्ताव किया। इस विभाग के लिए एक चीफ इंजीनियर तथा उसकी सहायता के लिए सुपरिन्टेंडिंग, एक्जीक्यूटिव तथा असिस्टेंट इंजीनियर आदि नियुक्त करने के लिए जांच कमीशन ने सिफारिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में पब्लिक वर्क्स विभाग खोला गया। धीरे धीरे लाई डलहौजी के शासन काल के अंत तक प्रत्येक प्रान्त में पब्लिक वर्क्स विभाग स्थापित हो गये। इन विभागों का कार्य इमारत, सड़क आदि बनवाना और संरक्षण करना था। केवल पंजाब और यू० पी० प्रान्तों में इस विभाग के अंतर्गत सिंचाई कार्य भी था। इस समय रेल बनाने के लिए जमीन की नाप आदि आरंभ हो चुकी थी तथा कुछ रेल लाइन बन भी चुकी थी।

सन् १८५४ ईस्वी में भारतीय सरकार ने पब्लिक वर्क्स विभाग के सेक्रेटरी का पद स्थापन कर केन्द्रीय पब्लिक वर्क्स विभाग की रचना की। रेल विभाग भी इस विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इसका कार्य प्रान्तीय पब्लिक वर्क्स विभाग का निरीक्षण, रेल संबंधी कार्यों की देख

के आधीन है। प्रधान इंजीनियर के नीचे कई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं। इनकी संख्या सब प्रांतों में एक सी नहीं है। मध्य प्रदेश में सड़क इमारत विभाग के तीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं। प्रत्येक अपने डिवीजन के कार्य का निरीक्षण करता है। इनके आधीन प्रत्येक जिले में एकजीक्यूटिव इंजीनियर होता है जिसका कार्य जिले की सरकारी इमारतों सड़कों आदि की मरम्मत तथा निर्माण के अनिवार्य म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्टबोर्ड के इमारत-सड़क विभाग का नियंत्रण करना है। यह म्यूनिसिपल इंजीनियर, वाटरवर्क्स इंजीनियर आदि की नियुक्ति में स्वीकृति देता है। इसका नियंत्रण इसी प्रकार है जिस प्रकार सिविल सर्जन का सफाई और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर है। एकजीक्यूटिव इंजीनियर के आधीन अनेको ओवरसियर सब ओवरसियर आदि हैं।

मिचार्ड विभाग—मिचार्ड विभाग के प्रांतीय मेजेटरी के आधीन भी डिवीजन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं। मध्यप्रान्त में इनकी भी संख्या ३ है। इनके नीचे भी एकजीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर सब ओवरसियर आदि अनेको कमचारी हैं।

मिचार्ड विभाग का कार्य नहरें खदवाना तथा उनको रक्षा का प्रबंध करना है। मिचार्ड की आवश्यकता तथा उपयोगिता प्राचीन समय में सामक मानते आये हैं। मुसलमान शासकों ने अनेको कुएँ, नालाब, नहरें आदि मिचार्ड के निमित्त बनवा कर दुर्भिक्ष रोकने के उपाय किये। अंग्रेजी काल में इस ओर विशेष उन्नति हुई है। देश में अनेको बड़ी बड़ी नहरें और जलाशय बनाने में सरकार ने सालाना धन देना आरम्भ किया। सन् १८९३ के पहिले वह रकम केवल ५० लाख रुपये थी। सन् १९ में ३५ लाख, १८९९ में ८५ लाख और उसके बाद बढ़ा कर १०५ लाख वार्षिक देना आरम्भ कर दिया है। सन् १९१८ तक मिचार्ड के लिये नहरें, जलाशय आदि बनवाने में लगभग १ अरब रुपये व्यय हो गया जिसमें २ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष सींची जाती थी। सन् १९ में मिचार्ड

का विचार हुआ। आधुनिक रेल की मड़कों उमी नक़्शे के आधार पर तैयार हुई हैं।

भारतीय रेलवे के इतिहास को ४ भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) सन् १८६९ के पूर्व, (२) १८६९ से १८८० तक, (३) १८८०-१८९३ और (४) सन् १८९३ के पश्चात्।

भारतीय रेलवे लाइन बनाने में भारत सरकार ने आरम्भ से ही योग दिया। उस संबंध में सरकार ने "गारंटी सिस्टम" की नीति आरम्भ की। सरकार ने रेलवे कंपनियों को खर्च की रकम पर ५ प्रतिशत व्याज देने की गारंटी दी और इस नीति के अनुसार सरकार ने इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में रेल खोलने का ठेका दिया। इसके अनुसार रेलवे कंपनियों से ज़मीन का मूल्य नहीं लिया गया। कंपनियों को यह गारंटी दी गई कि उन्हें लागत रकम पर ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवश्य ही लाभ होगा। लाभ में कमी होने पर सरकार ने उसे अपने कोष में पूरा करने का वचन दिया। इसमें अधिक लाभ होने पर कंपनी ने अधिक लाभ का आधा हिस्सा सरकार को देना स्वीकार किया। निश्चित समय (२५ या ५० वर्ष) के बाद कंपनी की रेल खरीद लेने का भी सरकार को अधिकार था। इसके अनिश्चित कंपनियों को यह भी अधिकार था कि वह कोई भी रेलवे लाइन ६ महीने का नोटिस देकर इच्छानुसार सरकार को बेच सकती थी। इसके अनिश्चित कंपनी भारत सरकार के ही आदेशानुसार रेल-मार्ग तथा नियमादि बनाने के लिये बाध्य थी। उसे अपना हिस्सा भी सरकार के पास जाँच पड़ताल के लिये भेजना अनिवार्य था। इस प्रकार कंपनियों ने कुछ ही वर्षों में लगभग १८०० मील रेल-मार्ग बनाया।

सन् १८६८ ई० में कलकत्ता और माउथ ईस्ट रेलवे, हानि होने के कारण सरकार को खरीद लेनी पड़ी। इसी समय से सरकार की निजी रेल होना आरम्भ हुआ। गारंटी सिस्टम के कारण सरकार को प्रति वर्ष बहुत हानि उठानी पड़ती थी। सन् १८६९ ईस्वी तक सरकार को १६६ ई

अथवा व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अपना अपना स्थान त्याग देने के एक वर्ष बाद ही इस समिति के सदस्य हो सकेंगे। सदस्य प्रायः पाँच वर्षों के लिये नियुक्त होंगे। अवधि पूरी हो जाने पर फिर नियुक्ति हो सकेगी, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं। समिति का निर्णय बोटों द्वारा होगा। चूँकि समिति में गवर्नर जनरल के मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक होगी और गवर्नर जनरल इच्छानुसार जिस सदस्य को चाहे हटा भी सकेगा इससे स्पष्ट है कि समिति बहक न सकेगी यही नहीं अपने कार्य क्षेत्र से संवन्ध रखने वाले मामलों में गवर्नर जनरल जो आज्ञा देगा उसका प्रतिपालन समिति को करना अनिवार्य होगा। किन्तु साधारण नीति फेडरल गवर्नमेन्ट ही निश्चित करेगी जिसके अनुसार “रेलवे आथारिटी” को आचरण करना होगा। रेलवे आथारिटी गवर्नर जनरल के निरीक्षण में वस्तुतः स्वाधीनता पूर्वक काम करेगी।

रेलवे आथारिटी की एक कार्यकारिणी होगी जिसका अधिपति “चीफ़ रेलवे कमिश्नर” होगा। उसकी सहायता के लिये एक अर्थ कमिश्नर (Financial Commissioner) रहेगा। इन दोनों की नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा। इनके अलावा रेलवे चीफ़ कमिश्नर की मिफ़ारिश से और उसकी सहायता के लिये अन्य कमिश्नर रेलवे आथारिटी नियुक्त कर देगी।

इन मस्यौओं के अलावा दो अन्य मस्यौएँ भी उल्लेखनीय हैं। एक का नाम है “रेलवे रेट्स कमिटी” (Railway rates committee) इसके सदस्यों को भी ग० जनरल ही नियुक्त करना है। इसका कर्तव्य है कि भाड़े महसूल और आवागमन संबंधी मामलों पर रेलवे आथारिटी को परामर्श दिया करे। दूसरी मस्यौ है “रेलवे ट्राइब्यूनल” (Railway Tribunal) जिसमें एक महापति और दो सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति भी ग० जनरल ही करेगा। महापति फेडरल कोर्ट के जजों में से ही पाँच वर्ष के लिए चुना जायगा। रेलवे ट्राइब्यूनल फेडरल रेलवे आथारिटी

दूरी और ताल के हिसाब ने उनसे मजदूरी पहले ले ली जाती थी^१। यह प्रबंध भी केवल पास रुपा का ही रूप था।

सन् १८३७ में एक महत्वपूर्ण एक्ट पास हुआ। इसी समय में भारतीय डाक का इतिहास प्रारंभ होता है। इस एक्ट के अनुसार बड़े बड़े स्थानों में जनता के लिए डाकघर खोले गये। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के अंतर्गत स्थानों में पत्रों के आवागमन का प्रबंध व्यवस्थित रूप से किया गया। इस समय भी पत्र भेजने की मजदूरी दूरी और वजन में ही निर्धारित की जाती थी। प्रेसीडेन्सी का पोस्टमास्टर प्रान्त भर के डाकखानों का नियंत्रण किया करता था तथा जिले के डाकघर कलेक्टर के निरीक्षण में थे।

तेरह वर्षों के बाद एक कमीशन डाकखानों की जांच के लिए बैठा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सन् १८५४ में भारतीय डाक एक्ट (Indian Postal Act) पास हुआ। इसी एक्ट के अनुसार भारत का आधुनिक डाक विभाग संगठित है। इसके अनुसार समस्त डाक विभाग के नियंत्रण के लिए एक डाइरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। पोस्टमास्टर जनरल का पद प्रेसीडेन्सी के पोस्टमास्टर में पृथक् कर दिया गया। हर एक प्रान्त में डाक विभाग के निरीक्षण के लिए एक पोस्टमास्टर जनरल, तथा छोटे प्रान्तों के लिए चीफ इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए। इसी समय में डाक के टिकटों का आरंभ हुआ जिसका मूल्य केवल वजन पर ही निर्धारित किया जाता था। इस समय में दूरों का प्रश्न उठा लिया गया।

ही रहा। कुछ समय तक लगान पर लगभग ५.३ प्रति शत भागन सरकार को रेल ने आमदनी होती रही। सन् ३१ से फिर रेल में घाटा होने लगा है। सन् ३४ में न घाटा ही हुआ और न लाभ ही।

रेलवे विभाग में अनेकों छोटे बड़े कर्मचारी हैं। सन् १९३३ में रेल विभाग में काम करनेवालों की कुल संख्या ३,१०,०३१ थी जिसमें १,२९३ यूरोपियन, ५,०८,०८२ हिन्दू, १,५२,८३५ मुसलमान तथा और १९,०१३ अन्य जातियों के कर्मचारी थे।

भारतवर्ष की रेलें संसार भर की प्रधान रेलों में गिनी जाती हैं। आजकल छोटी, बड़ी, ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की कुल २५ रेलवे कम्पनियाँ हैं। इनमें नार्वे वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, बाम्बे बरोदा सेंट्रल इंडिया रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे, मद्रास और मद्रन मराठा रेलवे, बर्मा रेलवे, बंगाल नार्वे वेस्टर्न रेलवे, आदि मुख्य हैं। रियासतों की रेलों में मिडान रेलवे, काठियावाड़ रेलवे तथा जोधपुर बीकानेर रेलवे विशेष उल्लेखन्य हैं।

डाक और तार

पुगने समय में ही भारतवर्ष में पत्र ले जाने और ले जाने के लिये प्रबंध था। यह सत्य है कि उस समय आवागमन के इतने सुमीत्रे न होने के कारण इसमें अनेको कठिनाई थी, और समय भी बहुत लगता था। मुसलमान-शासन-काल में भी पत्र, हरकाश या क़ामिद आदि के द्वारा भेजे जाते थे।

अंग्रेजी-शासन-काल में सन् १८३३ के पूर्व पत्रों के लिए व्ययस्थित प्रबंध न था। मुख्य शहरों में जहाँ कि सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी डाक के ले जाने का कुछ प्रबंध किया गया था। माधारण जनता के लिए यह प्रबंध न था। किसी व्यक्ति विशेष को यदि पत्र भेजना होता तो

की। आगरे का ताजमहल, दिल्ली, फ़तहपुर-सिकरी आदि स्थानों के प्राचीन क़िले और महल मुसलमान काल की कारीगरी के बढ़िया नमूने अभी तक हैं। इस काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई। ढाँके की मलमल दूर दूर देशों में जाकर भारत की कपड़ा बुनने की कला का परिचय देने लगी। चीन, तिब्बत, अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, ईरान आदि देशों से ही अधिकतर व्यापारिक संबंध था। मुसलमानी काल में देश की हस्तकला कदाचित् उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थी।

अँग्रेजी काल में देश के व्यापार कला-कौशल, व्यवसाय आदि में अद्भुत परिवर्तन हो गया। सर्वत्र आने जाने के मार्ग खुल जाने से एवं विदेशियों के संसर्ग से देश के व्यापार तथा ज्ञान में विशेष वृद्धि होने लगी। यूरोपीय जातियों ने भारत से सोना चाँदी आदि धातुओं के बदले मसाले, कपड़ा आदि ले जाकर अपने देशों में बेचना आरंभ किया। देश में वंबई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, कराँची आदि बंदरस्थानों की नींव पड़ी। स्थल मार्ग की अपेक्षा अब जलमार्ग के द्वारा ही व्यापार अधिकतर होने लगा। धीरे धीरे भारत का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आगया।

इसी समय संसार में नवीन युग आरंभ हुआ। मशीनों के प्रचार से हस्तकला सारे संसार में शिथिल पड़ गई। रेल तार आदि अनेकों आवागमन के नवीन साधनों का आविष्कार तथा प्रचार हुआ। समय पाकर भारतवर्ष में भी मशीनों का आगमन हुआ। देश में रेल तार आदि के बन जाने से व्यापार में भी उथल-पुथल हो गई। अनेकों नवीन नगर बसाये जाने लगे। कृषि की उन्नति के साथ ही जंगली पदार्थों जैसे लाख, लकड़ी, गोंद आदि के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी।

भारतवर्ष का विदेशों से व्यापार इधर कुछ वर्षों से घटता ही रहा। सन् १९२८ और १९२९ में प्रति वर्ष लगभग ४५० करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार होता था। सन् १९३२-३३ में यह केवल २७० करोड़ के

ग्यारहवाँ अध्याय

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

तहसील आदि के शासन करने के विधानों के सिवा कुछ ऐसी मस्थान् भी स्थापित की गई हैं जिनके मदम्य उसी स्थल के होते हैं जिन पर कि वे अनुशासन करती हैं, और जो निर्दिष्ट कामों का प्रबंध करती हैं। ऐसी मस्थान् हैं, म्युनिमिपैलिटी, जिला बोर्ड, लोकल बोर्ड और ग्राम पंचायतें। इन सब मस्थान् की गणना लोकल गवर्नमेंट के अन्दर की जाती है। पहले उन मस्थान् का निरीक्षण जिला के अफसरों के हाथ में था और उनके मदम्य में अधिकतर सरकार के नामजद किए हुए मदम्य होते थे। पहले उनको 'लोकल गवर्नमेंट' कहते थे किन्तु जब उनका प्रबन्ध जनता के चेतन हुए गैर सरकारी मदम्यों के हाथ में दे दिया गया और उनका मनोदन और निरीक्षण गैर सरकारी व्यक्तियों के सुपुर्द हो गया तब से इस विधान के लिए 'लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट' का प्रयोग होन लगा है।

स्थानीय शासन के लिए प्राचीन भारत में जनपद नागरिक समितियाँ और ग्राम मस्थान् आदि का होना ही प्रमाण मिलता है और कभी कभी उनके संगठन एवं कार्यक्रम ही जलद दिखाई देती हैं किन्तु उनका क्रमबद्ध ईर्नशास नहीं मिलता। उन्हीं मस्थान् का बदोवन इस श्रवण विप्लवा, राज्य परिवर्तन और राजनीतिक प्रगति का अदक गया। जब अंग्रेज भारत में आये उस समय ग्राम मस्थान् में कुछ न कुछ जीवन मन्त्रिण था क्योंकि वे ग्राम के अधिकारियों के हाथ में पड़कर दीर्घ रीति हो गई थी।

कम्पनी के राज्यत्व काल में इन संस्थाओं को पुनरुज्जीवित करने की कोई चेष्टा नहीं की गई। किन्तु उस समय कम्पनी आवश्यकतानुसार विलायती टांचे पर नगर शासन का कुछ संगठन करती रही। नुभीते के लिए हम इन संस्थाओं का वर्णन नागरिक शासन (Municipal Government) से ही आरम्भ करना उचित समझते हैं।

आजकल जिस प्रकार का संगठन म्यूनिसिपैलिटियों का है उसका आरंभ सन् १६८७ से होता है। उस साल इंग्लैण्ड के राजा जेम्स द्वितीय ने मद्रान शहर में एक "कारपोरेशन" (नागरिक मंड) और एक "मेयर की कोर्ट" स्थापित करने का अधिकार दे दिया। तदनुसार वहाँ लन्दन की नागरिक सभा के ढंग पर एक संस्था कायम की गई जिसको नगर हाल जेल्ड, नाली और स्कूल बनाने के लिए टैक्स कायम करने का अधिकार दिया गया। इसके मुख्य पदाधिकारी मेयर आल्डरमैन आदि थे। लोग न टैक्स देने का विरोध किया। इस संस्था की प्रार्थनानुसार उसका सरकार को सफाई के लिए कुछ वस्तुओं पर चगी वसूल करने का अधिकार 'म' सन् १७२६ में बर्क और कलकत्ता में भी मे मेयर वाटे मद्रान के ढंग पर कायम की गई। इस समय मेयर की अदालतों का अधिकार बनाना ही बनेर था।

गये। इतना सब होने पर भी जिला बोर्ड का चेयरमैन (सभापति) प्रायः जिला का हाकिम ही होता रहा। बहुत सी म्यूनिसिपैलिटियों में भी वही चेयरमैन होता रहा। इसका फल यह हुआ कि ये संस्थाएँ भी एक प्रकार से सरकारी संस्थाएँ रहीं और इनमें पूरी जिम्मेदारी और स्वानुकूल शासन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो सकी। उनका कर्तव्य प्रायः चेयरमैन (जिला अफसर) की हाँ में हाँ मिलाना और अनुशासन शिरोधार्य करना रहा।

यह परिस्थिति न्यूनाधिक सन् १९०८-९ तक कायम रही किन्तु उसके बाद में डिसेन्ट्रलाइजेशन कमीशन की सम्मति के अनुसार गैर सरकारी चेयरमैन चुनने की प्रथा एव चुने हुए सदस्यों की संख्या की वृद्धि कुछ शीघ्रता से होने लगी। सन् १९१८ में लार्ड चेम्सफर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि इन समस्याओं में अधिकांश समस्या चुने हुए सदस्यों की ही हो। सदस्यों को चुननेवालों (वोटर्स) की संख्या भी बढ़ा दी जाय। समस्याओं के सदस्य ही स्वयं गैर सरकारी चेयरमैन चुना करें। समस्याओं के अपनी जिम्मेदारी पर काम करने दिया जाय और सरकारी अफसर जहाँ तक बत पड़े उसमें हस्तक्षेप न कर। यद्यपि सन् १९०९ में डिसेन्ट्रलाइजेशन कमीशन ने आर सन् १९१० में गवर्नमन्ट आफ इंडिया ने गाँवों का भी मर्गाइन करने की प्रस्ताव - प्रस्तावित किया किन्तु उस पर कुछ विशेष कार्यवाही नहीं हुई। लार्ड चेम्सफर्ड ने फिर उस पर जोर दिया।

मान्डेय-चेम्सफर्ड मुद्दे पर कानून बनाने पर (१९११) सूबे की व्यवस्थापिका सभाओं ने लार्ड चेम्सफर्ड गवर्नमन्ट की ओर विशेष ध्यान दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि यह विषय भा. ट्रांसफर (Transferred) विषयों में आता था और गवर्नमन्ट के अधिकार में था। प्रत्येक सूबे की व्यवस्थापिका सभा ने लार्ड चेम्सफर्ड की अनुमति के अनुसार कानून बना डाला और उन पर लार्ड चेम्सफर्ड का कानून लागू होने लगी। अब लोकल समस्याओं के अधिकार उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दी गई और सरकारी हाथ उनसे करीब खींचा गया।

यद्यपि रियासत की प्रजा वहाँ के शासन के अधीन है और वहाँ का ही कानून उन पर लागू होता है किन्तु गवर्नमेंट इस बात को देखती रहती है कि उनपर घोर अन्याय अथवा अत्याचार तो नहीं होता। अन्याय और अत्याचार पाशविक दण्ड विधान, अथवा घोर अशान्ति या कुप्रवन्ध होने पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हो गई हैं जिनमें गवर्नमेंट ने या तो चेतावनी दी, या शासन राजा के हाथ से कुछ समय के लिए ले लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि राजा को गद्दी से हटा दिया और उसके स्थान में दूसरा गद्दी पर बैठा दिया। यदि राजा नाबालिग है तो भी जब तक वह बालिग न हो जाय तब तक गवर्नमेंट शासन का प्रवन्ध करती है। यदि देशी रियासत में किसी दूसरे देश का निवासी चला जाय तो उसकी भी रक्षा करने एवं उसके प्रति न्याय करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है। रियासतों में जहाँ पर ऐसी बस्नियाँ, रजोडेन्सी अथवा छावनियाँ हैं जिनमें अंग्रेज यूरोपियन आदि रहते हैं वहाँ गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती और कानून चलाती है—जैसे बंगलौर, मिकन्दराबाद, मऊ आदि। इसी प्रकार प्रायः जिस भूमिभाग में रेल ट्रैक चले जाती है वहाँ रेल की पटरियाँ स्टेशन आदि के पास के स्थानों पर गवर्नमेंट अपना कानून चलाती है। इसी प्रकार यदि किसी देशी रियासत का निवासी भारत में प्रायः अथवा भारत में बाहर जाय तो उसकी भी रक्षा का भार गवर्नमेंट का ही ऊपर है। भारत में बाहर जाने के लिए देशी रियासत के निवासी का गवर्नमेंट से ही पासपास लेना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि देशी रियासत किसी अन्य रियासत या बाहरी राज्या की साथ राजनैतिक अथवा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती है। अतएव यदि कोई देशी रियासत किसी प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध अथवा घन बाहरी रियासत से करना चाहे तो उसका गवर्नमेंट से आज्ञा लेनी पड़ती है और जिस तरह तक गवर्नमेंट आज्ञा दे उसी तरह तक वह सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार राज्या की सीमाओं की

